

Discover your divinity with us
A/C Showroom
ज्ञान गंगा ॐ मूर्ति माला केन्द्र
उजाला भवन स्टेशन रोड, दुर्ग
0788-4030383, 3293199

भगवान के दर्शन, श्रृंगार
मूर्तियां एवं समस्त
पूजन सामग्री
संगमरमर व पीतल की
मूर्तियां राशि रत्न
एवं उपरतन उपलब्ध

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

सामय दर्शन



रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

दुर्ग शहर में
सुप्रसिद्ध
ज्योतिषाचार्य
श्री दुर्ग उपरतन मा गुरुकुम्भी, श्री कामरुप, श्री भद्रकाली, श्री गणेश्वरी की
अतिम कृपा सम्पन्न दादा सम्बल स्वस्वामी का माता दर्शन हेतु

पं. एम.पी. शर्मा/
मो. 8109922001
फीस 251/- मात्र

पता:- श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय
सिकोला भाटा, सब्जी मार्केट के
सामने, धमधा नाका, दुर्ग

वर्ष 15, अंक 50

पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रूपये

दुर्ग, गुरुवार 25 दिसंबर 2025

www.samaydarshan.in

संक्षिप्त समाचार

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड
मामले में 2 प्रबंधकों को
जमानत मिली, एक की
याचिका खारिज

पुणे। गोवा की एक कोर्ट ने बर्द बाय रॉयटो लेन नाइट क्लब में आग लगाने के मामले में मंगलवार को 2 प्रबंधकों को जमानत दे दी, जबकि तीसरे प्रबंधक की याचिका खारिज कर दी है। जिला न्यायाधीश डीपी पाटकर ने तलब प्रबंधक राजवीर सिमानिया और प्रियांशु वाकरू की जमानत याचिका मंजूर की है। विवेक सिंह को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। तीनों को तलब में आग लगाने के एक दिन बाद 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। तलब के बाद प्रबंधक सिमानिया और गैर तलब वाकरू को जमानत देते हुए कोर्ट ने कड़ी शर्त लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी अग्निकांड मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नही भंडावण, न धमकावण न प्रभावित करने। दोनों पूर्ण लिखित अनुमति के बिना नही छोड़े और जांच में सहयोग करेंगे। आरोपण या अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल होने तक दोनों नही लेने में एक बार, पहले सुधार को, जांच अधिकारी या अज्ञान पुलिस थाने आगो गोवा के अपराध स्थित नाइट क्लब में 6 दिसंबर को रात आठ बजे की जगह से भीषण आग लग गई थी, जिसमें 5 पर्यटक और 20 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। घटना के कुछ घंटे बाद ही तलब के मालिक गौरव सुयार और सौरभ तुल्य शर्मा के फुटबल फील्ड में गए थे, जिन्हें वहां से निवृत्त कर आगत लाया गया। दोनों अभी गोवा में पुलिस की हिरासत में हैं। मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।

तेलंगाना में उप-परिवहन
आयुक्त के पास 100
करोड़ रुपये से अधिक की
संपत्ति, जांच शुरू

हैदराबाद। तेलंगाना में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। राज्य के महानगर जिले में उप-परिवहन आयुक्त गुरु किरण के पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई है, जिसकी जांच तेलंगाना की भ्रष्टाचार विरोधी द्यूरे (एसीबी) ने शुरू की है। बताया जा रहा है कि उनके पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। उनके खिलाफ आय के स्रोतों के अनुपात से कहीं अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया है। एसीबी ने किरण के घर और उनसे जुड़े 11 अन्य ठिकानों में जांच के बाद कई दरवाजे बगल दिए हैं। इसमें संग्रहीत 31 एकड़ कृषि भूमि, निजामाबाद में 10 एकड़ व्यावसायिक जमीन, 3,000 वर्ग गज का फर्नीचर शोखन, लाहरी इन्टरनेशनल होटल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी, 137 करोड़ रुपये का फीज बैंक बेलेंस, 1 किलो से ज्यादा आभूषण, इनोवा क्रिस्टा, सैंड सिटी शांति है। संपत्तियों का दस्तावेजी तूट 12.72 करोड़ है, जबकि जन्मी कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है। जांच एजेंसी का आरोप है कि अधिकारी ने सरकारी सेवा में रहते ही यह संपत्ति बनाई है। वह किस पद पर तैनात थे, उस पैके के आधार पर जांच के दौरान 1 से 1.25 लाख रुपये होता है। जांच एजेंसी ने गुरु किरण के खिलाफ संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया है। सभी धाराएं अग्रिम शर्तों के अधीन चलाने और आपराधिक दुराचार से संबंधित हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट एयर
प्यूसीफायर पर 18 प्रतिशत
जीएसटी से नाराज, केंद्र
सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखे सवाल दामे। उसने हवा शुद्ध करने वाले एयर प्यूसीफायर उपकरण पर 18 प्रतिशत वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को लेकर नाराजगी जताई और पूछा कि वायु आपातकाल में भी उपकरण पर इतना जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि वह इस जीएसटी को कुतर्क क्यों नहीं घटा सकती? मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश तुषार राव गंडेला की खड़पी ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते समय की। याचिका में एयर प्यूसीफायर को विकसित उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की मांग की गई थी, ताकि उपकरण 5 प्रतिशत के निम्न जीएसटी दर में आ जाए। कोर्ट के सवाल पर केंद्र ने जवाब देते के लिए उचित समय मांगा तो कोर्ट ने कहा, उचित समय का क्या मतलब है? जब हजारों लोग मर जाते हैं? कोर्ट ने कहा, इस शहर के हर नागरिक को स्वच्छ हवा चाहिए और आप वह उपलब्ध नहीं कर पाए हैं। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि उन्हें वायु शोधक उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने तत्काल शहर की संभावना जताई और कहा कि इस हवाई आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इसे अस्थायी उपकरण के रूप में छूट क्यों नहीं दी जा सकती? जनहित याचिका अधिकांश कपिल मदन दास की गई है।

महिला विकास की नई इबारत लिख रही है साय सरकार

छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण का नया युग, आगामी वर्ष 'महतारी गौरव वर्ष' घोषित

समर्थन और आशीष से ही
जनसेवा के कार्यों को नई ऊर्जा
और दिशा मिलती है- सीएम

रायपुर (समय दर्शन)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्ष को 'महतारी गौरव वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार निरन्तरने फैसले ले रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 तैयार किया गया है। विकसित छत्तीसगढ़ में



महिलाओं की सशक्त भागीदारी को देखते हुए राज्य में आगामी वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रथानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार निरन्तरने फैसले ले रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 तैयार किया गया है। विकसित छत्तीसगढ़ में

व्यक्त किया कि यह वर्ष छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति के नेतृत्व, सहभागिता और सम्मान का एक नया अध्याय लिखेगा, जो विकसित, समरस और सशक्त छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव बनेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार को सबसे बड़ा आशीर्वाद माताओं और बहनों से प्राप्त होता है। उनके विश्वास, समर्थन और आशीष से ही जनसेवा के कार्यों को नई ऊर्जा और दिशा मिलती है। इसी भावनात्मक और सामाजिक दायित्वबोध से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का पहला वर्ष 'विश्वास वर्ष' के रूप में समर्पित रहा, जिसमें शासन और जनता के बीच भरोसे की पुनर्स्थापना हुई।

दूसरा वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित 'अटल निर्माण वर्ष' के रूप में मनाया गया, जिसके दौरान आधारभूत ढांचे के सुदृढीकरण, सामाजिक विकास और जनकल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य पूरे हुए। अब सेवा का आगामी वर्ष मातृशक्ति को समर्पित 'महतारी गौरव वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें राज्य की सभी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का केंद्रबिंदु माताएँ और बहनें होंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर किए गए कार्यों ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पटल पर एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया है। सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य,

राज्य की विकास यात्रा के केंद्र में महिलाएँ

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूती देने वाली महतारी वंदन योजना के अंतर्गत राज्य की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 22 किशतों में 14,306 करोड़ 33 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। महिला कल्याण के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य की विकास यात्रा के केंद्र में महिलाएँ हैं। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने के उद्देश्य से रजिस्ट्री शुरू में 1 प्रतिशत की छूट, 368 महतारी सड़कों का निर्माण, मितामिनो और अगलबाड़ी कार्टकटऑफ के मानदेय का ऑनलाइन गुणानुमान जैसे निर्णयों ने सुशासन और पारदर्शिता को और सुदृढ किया है। स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 42,878 महिला समूहों को 12,946.65 लाख रुपये का सहायता पैका प्रदान किया गया है। वहीं, बस्तर सहित छह जिलों में टैडी-टू-ईट का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया है।

आजीविका और निर्णय क्षमता को अपनी नीतियों का मूल आधार बनाते हुए सामाजिक-आर्थिक बदलाव को एक नई दिशा तय की है। महिला आजीविका के नए अवसर सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, नवाबिहान योजना, डिजिटल सखी, दीदी ई-रिक्शा सामाजिक-आर्थिक बदलाव को एक नई दिशा तय की है। महिला आजीविका के नए अवसर सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री

बंद कमरे में अंगीठी जलाकर साए 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत

पेंट का काम करने आए थे सभी

कुरुक्षेत्र, 24 दिसंबर (आरएनएस)। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिपली रोड स्थित होटल स्टीलिंग रिसोर्ट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोना पांच लोगों के लिए काल बन गया। बीती रात बंद कमरे में अंगीठी की गैस से दम घुटने के कारण वहां सो रहे सभी पांच मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर होटल में चल रहे निर्माण कार्य के तहत रंग-रोशन का काम करने आए थे। जानकारी के अनुसार, दिन भर काम करने के बाद लेबर क्लास के



ये पांच लोग रात को एक ही कमरे में सोए थे। कड़के की ठंड से बचने के लिए उन्होंने कमरे में अंगीठी जला रखी थी और दरवाजा व खिड़की बंद कर लिए थे। सुबह जब काफी देर तक कमरे से कोई बाहर नहीं निकला, तो होटल स्टाफ को संदेह हुआ। सफाई कर्मी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद जब

स्टाफ ने खिड़की से झांकर देखा तो अंदर कोई हरकत नहीं हो रही थी। अनहोनी की आशंका होने पर होटल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही थाना शहर एसएचओ दिनेश राणा और सेक्टर-7 चौकी इंचार्ज कमल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। होटल के सुरवाहजर उषेंद्र ने पुलिस को बताया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का ठेकेदार नूर अपनी लेबर के साथ यहां पेंट का काम करने आया था। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में ले लिया है।

महाराष्ट्र में 20 साल बाद साथ आए उद्धव और राज ठाकरे, मिलकर लड़ेंगे बीएमपी चुनाव

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में 20 साल बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (बीएमपी) के प्रमुख राज ठाकरे साथ आ गए हैं। उन्होंने बुधवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आले साल होने वाले बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमपी) चुनावों में साथ उतरने का फैसला किया है। हालांकि, अभी सीट की घोषणा नहीं की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ठाकरे भाईयों ने अपनी-अपनी पंक्तियों और बेटों के साथ शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा, अगर हम लड़ते रहे तो यह हुतात्मा



का अपमान होगा। कोई भी मुंबई को मराठी मानुष से नहीं छीन सकता। भाजपा ने तब कहा था बेटों तो कांटेंगे। अब मैं मराठी मानुष को चुनौती दे रहा हूँ, अगर वे अब लड़खड़ाए तो वे विभाजित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मराठी अस्मिता की विरासत को न छोड़ें, अगर लोग टूट गए तो बिखर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम एकसाथ रहने के लिए साथ आए हैं। राज ठाकरे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, महाराष्ट्र किसी भी गलतफहमी या लड़ाई से बड़ा है। हमारी शुरुआत यहाँ से हुई है। हम यहाँ रह बताने के लिए नहीं आए हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आज की बैठक के बाद हम अन्य निगमों के लिए घोषणा करेंगे, लेकिन मुंबई का महापौर मराठी होगा और हमारी पार्टी से ही होगा। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में बैठे दो लोगों को रोकने आए हैं। दोनों पार्टियाँ मुंबई के अलावा ठाणे, मीरा भायंदर, कल्याण डोंबिवली और नासिक सहित 5 प्रमुख नगर निगमों में एक साथ चुनाव लड़ेंगी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बताया था कि उद्धव और राज ठाकरे मुंबई के अलावा पुणे, नासिक और कल्याण-डोंबिवली जैसे स्थानों पर भी रैलियाँ कर सकते हैं।

8 करोड़ के इनामी पोस्टरों का दिखा खौफ 22 माओवादियों ने एक साथ किया सरेंडर

ओडिशा में नक्सलियों की कमर टूटी

अनुगुल (एजेंसी)। ओडिशा में नक्सल विरोधी अभियान को एक बड़ी और निर्णायक कामयाबी मिली है। मलकानगिरी पुलिस के सामने 22 खूंखार माओवादियों ने सामूहिक रूप से हथियार डालते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है। इसे इस वर्ष राज्य में माओवादियों का पहला और सबसे बड़ा सरेंडर माना जा रहा है, जिसने लाल गलियारों में हलचल मचा दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सफलता सुरक्षाबलों के बहते दबाव और रणनीतिक

मनोवैज्ञानिक चार नतीजा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आत्मसमर्पण करने वालों में संगठन के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी शामिल हैं। इनमें एक संभागीय समिति सदस्य, छह सहायक समिति व उपसमिति सदस्य और 15 पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन नक्सलियों पर सरकार ने 5.5 लाख रुपये से लेकर 27.5 लाख रुपये तक का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस का कहना है कि पिछले सप्ताह ही जिले भर में और सार्वजनिक स्थानों पर 8 करोड़ रुपये से अधिक के इनामी माओवादियों के पोस्टर चस्पा किए गए थे।

इसरो ने सबसे बड़ा कमर्शियल सैटेलाइट सफलतापूर्वक किया लॉन्च

भारत के कमर्शियल स्पेस सेक्टर को नई मजबूती

श्रीहरिकोटा (एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार सुबह अपने ताकतवर एलवीएम3-एम6 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 कमर्शियल सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह मिशन आज सुबह 08:54 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से किया गया। यह लॉन्च भारत की जमीन से किया गया अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल सैटेलाइट मिशन माना जा रहा है, जिससे वैश्विक स्पेस मार्केट में भारत की मौजूदगी और



मजबूत हुई है। ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट एएसटी स्पेस मोबाइल द्वारा खास तौर पर सीधे सामान्य स्मार्टफोन तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना

किसी अतिरिक्त डिव्हाइस के 4जी और 5जी कनेक्टिविटी देने में सक्षम है। करीब 6,100 किलो वजनी यह सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचने के बाद 223 वर्ग मीटर का विशाल एंटीना खोलेंगा, जो कमर्शियल क म्युनिक के शान

सैटेलाइट्स में अब तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है। इस मिशन में इस्तेमाल किया गया एलवीएम3 रॉकेट इसरो का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है, जिसे 96%बहुबल% भी कहा जाता है। यह तीन चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेज शामिल हैं। 43.5 मीटर ऊंचा और 640 टन वजनी यह रॉकेट पहले ही चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और वनवचन जैसे अहम मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और तकनीकी मजबूती बार-बार साबित होती रही है। लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद

वीडियो देख भड़के लोग नेशनल खेलने गए और टॉयलेट के पास बिठाया' नन्हे पहलवानों के साथ शर्मनाक सुलूक

भुवनेश्वर (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में आयोजित 69वां राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गए ओडिशा के होनहार खिलाड़ियों के साथ घोर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। राज्य का नाम रोशन करने निकले इन बच्चों को सम्मान तो दूर, ढंग से सफर करना भी नसीब नहीं हुआ। मास एजुकेशन विभाग की कथित बर्दशतजामी के चलते 18 युवा खिलाड़ियों, जिनमें 10 लड़के और 8 लड़कियां शामिल हैं, को कड़के की ठंड में ट्रेन के सामान्य डिब्बे में टॉयलेट के पास और फर्श पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। आरोप है कि विभाग ने समय रहते इन खिलाड़ियों के लिए कन्फर्म टिकट का इंतजाम नहीं किया था। इस बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे ओडिशा में रोष पैदा कर दिया है। वीडियो में साफ देखा

रजयसभा सांसद सुलता देव ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'डबल इंजन सरकार' की विफलता बताया है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक है और सरकार 17 महीनों में ही फेल साबित हो चुकी है। सांसद ने भावुक होते हुए कहा, जो बच्चे ट्रेन में बाथरूम के पास बैठकर गए, उनके मासूम दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा? मां-बाप लाड-प्यार से बच्चों को पालते हैं, अगर आप उन्हें सम्मानजनक तरीके से नहीं ले जा सकते, तो मत ले जाइए, लेकिन यू बेइज्जती मत कीजिए। उन्होंने सवाल

किया कि क्या कोई अधिकारी अपने बच्चों को इस तरह टॉयलेट के पास बिठाकर सफर करा सकता है? सुलता देव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे खुद ओडिशा से हैं, क्या उन्हें जानकारी नहीं थी कि बच्चों का रिजर्वेशन नहीं है? सांसद ने सुझाव दिया कि बच्चों के अभिभावकों को विभाग पर केंस करना चाहिए और अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिक प्रताड़ना के बाद बच्चों से मेडल की उम्मीद करना तो दूर, वे ठीक से खेल भी नहीं पाएंगे। फिलहाल, स्कूल एवं जनशिक्षा विभाग की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन जनता की मांग है कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में खिलाड़ियों के साथ ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।

स्मृति मंधाना के पिता की तबियत बिगड़ी, शादी अनिश्चितकाल के लिए टली

सांगली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बलेबाज स्मृति मंधाना और गायक पलाश मुख्तल की प्रस्तावित शादी टल गई है। मंधाना के पिता की अचानक बिगड़ी तबियत की वजह से शादी को टाला गया है। इसकी पुष्टि मंधाना के प्रबंधक तुहिन मिश्रा ने की। मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, सुबह मैं जब स्मृति मंधाना के पिता नाश्ता कर रहे थे उसी समय उनकी तबियत खराब होने लगी थी। हमने थोड़ी देर इंतजार किया कि शायद सामान्य वे सामान्य हो जाए। लेकिन, सुधार न होता देख उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उन्होंने कहा, मंधाना अपने पिता के बहुत नजदीक हैं। इसलिए अपने पिता को पूरी तरह ठीक होने तक उन्होंने शादी के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। मंधाना और पलाश मुख्तल की शादी सांगली में रविवार शाम 4 बजे होने वाली थी। शादी सांगली के समडोली रोड पर मंधाना फार्म हाउस में होने वाली थी। शादी के लिए मंधाना परिवार लंबे समय से तैयारियों में जुटा हुआ था।

रायपुर (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालिका गृह कॉडगांव की कुमारी योगिता मंडवों को 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, खेल/जूड़ो के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो कि माता पिता की मृत्यु 4 वर्ष की उम्र में हो गई थी, उसके बाद उसकी परवरिश बालिका गृह कॉडगांव में हुई, विपरीत परिस्थिति में भी अपनी मेहनत और लगन से योगिता ने मात्र 13 वर्ष की आयु में मात्र 14 वर्ष की उम्र में उसने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल करना शुरू किया। जूडो में लगातार बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु चुना



जा सकता है कि छोटे-छोटे बच्चे ट्रेन के टॉयलेट के पास दयनीय स्थिति में बैठें हैं। खेल प्रेमियों और अभिभावकों ने तीखे सवाल उठाए हैं कि जब ये बच्चे राष्ट्रीय मंच पर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा दयम दर्जे का व्यवहार क्यों किया गया। लोगों का कहना है कि यह घटना न सिर्फ प्रशासनिक संवेदनहीनता को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सिस्टम की नजर में युवा प्रतिभाओं के सम्मान की कोई कीमत नहीं है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मी कर दिया है। बीजू जनता दल (बज्जद) की

GAIL का 10,500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बना प्रमुख आकर्षण

छत्तीसगढ़ में कौशल-एकीकृत औद्योगिक विकास को मिल रही नई गति - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। भविष्य-उन्मुख कौशल विकास के साथ औद्योगिक विकास को सुदृढ़ रूप से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास विभाग एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 23 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ स्किल टेक का आयोजन किया गया। यह उद्योग-केंद्रित निवेश कार्यक्रम प्रधानमंत्री सेतु योजना (PM SETU) के अंतर्गत कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन (MoUs) हस्ताक्षरित किए गए तथा निवेश आमंत्रण पत्र जारी किए गए। कुल मिलाकर 13,690 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश सामने आए हैं, जिनसे राज्य में 12,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। ये निवेश विभिन्न क्षेत्रों में कौशल-आधारित

रोजगार को मजबूती प्रदान करेंगे।

कौशल-आधारित औद्योगिक विकास की धुरी बना गेल का प्रोजेक्ट- निवेश प्रतिबद्धताओं में गेल (GAIL) का प्रस्तावित गैस-आधारित उर्वरक संयंत्र राज्य के लिए एक प्रमुख एवं सबसे बड़े औद्योगिक प्रस्तावों में से एक के रूप में उभरकर सामने आया। लगभग 10,500 करोड़ रुपये के प्रथम चरण निवेश तथा 1.27 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) यूरिया उत्पादन क्षमता के साथ यह परियोजना छत्तीसगढ़ को देश के डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल एवं उर्वरक मानचित्र पर सशक्त रूप से स्थापित करेगी। यह प्रस्तावित परियोजना गेल की मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (MNJPL) के साथ प्लान की गई है, जो अनुकूल तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होगी। यह परियोजना राजनांदगांव जिले के बिजेतला क्षेत्र में 400 एकड़ से अधिक



भूमि पर प्रस्तावित है, जबकि 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि एक समर्पित टाउनशिप के लिए आरक्षित की गई है। परियोजना में भविष्य में मांग एवं अधोसंरचना की उपलब्धता के अनुरूप क्षमता विस्तार का भी प्रावधान रखा गया है।

परियोजना के संचालन में आने के पश्चात लगभग 3,500 प्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके साथ ही संचालन, तकनीकी

सेवाओं, लांजिस्टिक्स, मटेनेंस तथा संबद्ध क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन की निरंतर मांग उत्पन्न होगी, जो राज्य के कौशल-एकीकृत औद्योगिकीकरण के दृष्टिकोण को और सशक्त करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा— छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल निवेश, रोजगार और कौशल को आपस में जोड़ने पर आधारित है। छत्तीसगढ़ स्किल टेक जैसे

मंचों के माध्यम से हम निवेशकों के विश्वास को जमीनी स्तर पर परिणामों में बदल रहे हैं, ताकि राज्य में कुशल रोजगार के अवसर सृजित हों। इसके पीछे स्पष्ट नीतियाँ और प्रभावी क्रियान्वयन क्षमता हमारी ताकत है। गेल के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ स्किल टेक में परिधान एवं वस्त्र, फर्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग, सोलर पैनेल निर्माण तथा अन्य उभरते (सनराइज) क्षेत्रों में भी निवेशकों की मजबूत रुचि देखने को मिली। ये सभी क्षेत्र राज्य की कौशल विकास प्राथमिकताओं एवं रोजगार सृजन लक्ष्यों के अनुरूप हैं। कार्यक्रम के दौरान जशपुर में स्थापित आदित्य बिरला स्किल सेंटर को भी एक महत्वपूर्ण उद्योग-प्रेरित कौशल पहल के रूप में रेखांकित किया गया, जिसका उद्देश्य पारंपरिक एवं उभरते क्षेत्रों में कार्यबल की क्षमताओं को अपस में जोड़ने पर आजीविका के अवसर बढ़ाना है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल प्रांतीय मझवार महासम्मेलन में हुए शामिल



रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सरगुजा जिले के रामगढ़ उदयपुर में आयोजित प्रांतीय मझवार महासम्मेलन में शामिल होकर समाज के लोगों से सीधा संवाद किया। श्री अग्रवाल ने उदयपुर विकासखंड में सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा करते हुए अपने संबोधन में कहा कि मझवार समाज ने सदैव परिश्रम, ईमानदारी और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के बल पर सरगुजा अंचल की अस्मिता एवं विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और इस दायित्व को पूरी संवेदनशीलता के साथ निभाया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और युवा पीढ़ी की शिक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर विकास की मुख्यधारा में अग्रसर हो सकता है। मंत्री ने उपस्थित छात्र-छात्राओं से आग्रह किया कि वे उच्च शिक्षा और कौशल विकास के उल्लेख्य अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, ताकि रोजगार और स्वरोजगार दोनों के लिए रास्ते खुल सकें।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने मझवार समाज की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, लोकगीत,

नृत्य और रीति-रिवाजों का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिकता के साथ-साथ अपनी जड़ों से जुड़ाव बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय और पारंपरिक समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और प्रसार के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, जिनमें उत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव और लोककला मंचों का विशेष योगदान है। श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि पर्यटन विकास के साथ स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे न केवल क्षेत्र की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे सरकार के साथ समन्वय कर अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताओं को चिन्हित और संरक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री राजेश अग्रवाल ने आगे कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। वंचित और पिछड़े समुदायों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान हमारी प्राथमिकता है और मझवार समाज सहित सभी संवेदनशील वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

तीन परिवारों को मिला प्रधानमंत्री बीमा योजना का सहारा : बीमा राशि का किया गया भुगतान

रायपुर। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री बीमा योजना ज़रूरतमंद परिवारों के लिए कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर एक मजबूत संबल दे रही है। आकस्मिक दुर्घटना अथवा असमय निधन की स्थिति में यह योजना न केवल आर्थिक राहत देती है, बल्कि प्रभावित परिवारों को जीवन की कठिन घड़ी से उबरने का साहस भी प्रदान करती है। इसी क्रम में कोंडागांव जिले के दो परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक परिवार को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जिससे आश्रितों परिवारों आर्थिक राहत मिल सकी। ग्राम उमरगांव निवासी पूर्णिमा मांडवी को उनके पति स्वर्गीय रतन राम मांडवी के निधन के पश्चात बीमा राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार ग्राम सिंघनपुर, पोस्ट उमरगांव, जिला कोंडागांव निवासी श्री साधुराम को उनकी पत्नी स्वर्गीय धरमिनी बाई, जिनकी मृत्यु पानी में डूबने से हो गई थी, के आकस्मिक निधन पर बीमा



सहायता दी गई। वहीं, ग्राम डूमर गोदारा निवासी मंगलदेई मांडवी को उनके पति स्वर्गीय आंदोराम मांडवी, जिनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी, के निधन के बाद हितग्राहियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि का लाभ मिला। तीनों मामलों में पात्र हितग्राहियों के प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपये की बीमा राशि स्वीकृत की गई। गत दिवस जिला प्रशासन द्वारा तीनों परिवारों के

आश्रितों को चेक प्रदान किए गए।

लाभार्थियों ने बीमा राशि प्राप्त होने पर शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में मिली यह सहायता उनके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। उन्होंने बताया कि पति की मृत्यु के बाद परिवार के सामने आजीविका और बच्चों की शिक्षा जैसी कई चुनौतियाँ खड़ी हो गई थीं, ऐसे में बीमा राशि से उन्हें काफी राहत मिली है।

कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने खैरबार और जुनाडीह में बहुप्रतीक्षित विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

रायपुर। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के खैरबार में समूह जल प्रदाय योजना और लखनपुर विकासखंड के जुनाडीह में 50 सीटर आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के निर्माण कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया। लगभग 4604.12 लाख रुपये की लागत से खैरबार में होने वाले बहुप्रतीक्षित समूह जल प्रदाय योजना से अंबिकापुर क्षेत्र के 32 ग्रामों को शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छ पेयजल हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गांव इस सुविधा से वंचित न रहे। समूह जल प्रदाय योजना के पूर्ण होने पर इन 32 ग्रामों की



बड़ी आबादी को हँडपंप और असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, साथ ही जलजनित बीमारियों में भी कमी आएगी। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से अपील की कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग देते हुए जल संचयनाओं की दीर्घकालिक सुरक्षा में भी भागीदार बनें। लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम जुनाडीह में 1.89 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 50 सीटर आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक

छात्रावास का भूमिपूजन करते हुए मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा के बिना समग्र विकास संभव नहीं है। यह छात्रावास दूरस्थ आदिवासी इलाकों के मेधावी और इच्छुक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें शहरोँ तक बार-बार आवागमन की कठिनाइयों से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासी अंचलों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा केवल संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। छात्रावास के संचालित हो जाने पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हाईस्कूल एवं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलेगा, जिससे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास गति पकड़ेगा।

सुशासन, संवेदना और सुरक्षा : श्रमिक हित में छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष

रायपुर। सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की संकल्पबद्ध प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन का श्रम विभाग विगत दो वर्षों में इसी सुशासन की भावना को धरातल पर साकार करता हुआ दिखाई देता है। इस अवधि में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, उनके जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने तथा उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए अनेक ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम उठाए गए हैं।

विष्णु के सुशासन की स्पष्ट झलक श्रम विभाग द्वारा अपनाए गए डिजिटल नवाचारों में दिखाई देती हैं। प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से समस्त नस्त्रियों का संधारण ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। विभागीय योजनाओं और सेवाओं को आमजन के लिए सरल,



सुलभ और पारदर्शी बनाने हेतु एक आधुनिक, यूजर-फ्रेंडली विभागीय वेबसाइट विकसित की गई है। श्रमिकों की सुविधा को केंद्र में रखते हुए तैयार किया गया 'श्रमव जयते' मोबाइल ऐप श्रमिक पंजीयन, योजनाओं में आवेदन तथा श्रमिक पलायन की ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है, जो डिजिटल सुशासन की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। राज्य के नवगठित जिलों तक श्रम विभाग की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने

के लिए पाँच नवीन श्रम पदाधिकारी कार्यालयों की स्थापना हेतु 20 पदों का सृजन किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2024-25 के दौरान श्रमायुक्त संगठन अंतर्गत श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पदों पर कुल 32 नई नियुक्तियाँ की गईं। इन प्रयासों से न केवल विभागीय कार्यों में गति आई, बल्कि श्रमिकों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ भी सुनिश्चित हुईं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्रम कानूनों में आवश्यक

और संतुलित सुधार करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और श्रमिक हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 के प्रभावी क्रियान्वयन से छोटे व्यापारियों को राहत मिली, वहीं नियत कालिक नियोजन कर्मकार की नई श्रेणी ने रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोले। राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत लागू किए गए छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन एवं विविध कल्याण योजनाओं के माध्यम से अवैधानिक हड़ताल पर नियंत्रण, छोटे अपराधों में समझौते तथा लघु उद्योगों को सूट जैसे प्रावधान किए गए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में रात्रि पाली में महिला कर्मकारों के सशर्त नियोजन की अनुमति देना सरकार की प्रगतिशील और संवेदनशील सोच को दर्शाता है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में श्रमिक कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की मानवीय प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। विभिन्न श्रम मंडलों के माध्यम से दो वर्षों में 11.03 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया तथा 27.33 लाख

श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस अवधि में 784.73 करोड़ रुपये से अधिक की राशि श्रमिक कल्याण पर व्यय की गई, जो यह दर्शाती है कि यह सरकार आंकड़ों से आगे बढ़कर संवेदना के साथ श्रमिकों के जीवन में बदलाव ला रही है। 24म7 संचालित अवसरों के द्वार खोले। राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत लागू किए गए छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन एवं विविध कल्याण योजनाओं के माध्यम से अवैधानिक हड़ताल पर नियंत्रण, छोटे अपराधों में समझौते तथा लघु उद्योगों को सूट जैसे प्रावधान किए गए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में रात्रि पाली में महिला कर्मकारों के सशर्त नियोजन की अनुमति देना सरकार की प्रगतिशील और संवेदनशील सोच को दर्शाता है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में श्रमिक कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की मानवीय प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। विभिन्न श्रम मंडलों के माध्यम से दो वर्षों में 11.03 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया तथा 27.33 लाख

संक्षिप्त समाचार

क्रोमा के अनुसार : अब प्रीमियम और सेहतमंद होगा इंडिया!

मुंबई: टाटा ग्रुप के विश्वसनीय ओम्नी-चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर, क्रोमा ने आज अपनी 'इंटर-एंड कंज्यूमर ट्रेड्स 2025' रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट इस बात का दिलचस्प विवरण पेश करती है कि इस साल भारतीयों ने तकनीक और घरेलू उपकरणों के अपग्रेड को किस तरह अपनाया है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के अनुसार, भारतीय ग्राहक अब क्रोमा के देशव्यापी ऑफलाइन और ऑनलाइन नेटवर्क पर मल्टी-ब्रांड लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, प्रीमियम फैंस और स्मार्ट सुविधाएँ और स्वास्थ्य पर केंद्रित उपकरणों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

मोबाइल अपग्रेड का रहा बोलबाला!- क्रोमा के 2025 'इंटर-एंड कंज्यूमर ट्रेड्स' के अनुसार, स्मार्टफोन की कुल बिक्री में साल-दर-साल बड़ी बढ़त दर्ज की गई, लेकिन असली कहानी ग्राहकों के बदलते व्यवहार में छिपी है। बिकने वाले हर तीन नए फोन में से एक 20,000-30,000 के प्रीमियम बैंड में था, और लगभग हर पांच में से एक फोन फ्लैगशिप या सुपर-फ्लैगशिप मॉडल था। 50,000-58,000 जैसे विशेष ग्राइस ब्रैकेट की बिक्री में 300% से अधिक का उछाल आया। यह स्पष्ट संकेत है कि, भारतीय अब तकनीकी को केवल ज़रूरत नहीं बल्कि अपनी 'पहचान' मान रहे हैं और बेहतर अनुभवों के लिए अधिक खर्च करने को तैयार हैं। भारत अब सही मायने में एक डिजिटल-फर्स्ट देश बन गया है, जहाँ कंटेंट क्रिएटर्स की बढ़ती संख्या, गेमिंग का शौक और एआई व उनका कैम्पेन फैंस ग्राहकों की पहली प्राथमिकता बन गए हैं।

प्रीमियम कंज्यूमर का बढ़ा क्रैज: बंगलुरु बना हाई-एंड लैपटॉप का गढ़!- लैपटॉप बाजार ने कुल मिलाकर दो अंकों की शानदार बढ़त दर्ज की है, जिसमें हर श्रेणी में प्रीमियम अनुभव की ओर स्पष्ट झुकना देखा गया। एआई पीसी अब 'जेन-जी' की 'हमल इकोनॉमी' और 'जेन अल्ट्रा' की 'एआई-नेटिव' जीवनशैली को नया आकार दे रहे हैं। एप्पल के एम4 चिप ने प्रीमियम बेंचमार्क सेट किया है, तो वहीं NVIDIA ने गेमिंग की दुनिया में जबरदस्त उछाल ला दिया है। इसके साथ ही अब लैपटॉप की एक नई श्रेणी उभर कर आई है: एआई-एनेबल्ड, एआई नेक्स्ट-जेन और गेमिंग पीसी। भारत का 'सिलिकॉन ट्राइड'-बंगलुरु, मुंबई और दिल्ली-इस एआई-फर्स्ट लहर का नेतृत्व कर रहे हैं। यह तकनीकी विकास के एक नए दौर का संकेत है।

एक नई नागिन; एक नया युद्ध; एक नए युग का सूत्रपात, लौट रही है 'नागिन' 27 दिसंबर को

मुंबई। 'नागिन कब आएगी?' — इस सवाल ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, जिसका जवाब अब मिल चुका है। तीन साल के लंबे इंतजार के बाद, भारत की सबसे प्रतिष्ठित फैंटेसी गाथा लौट आई है। जियोस्टार और एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स 27 दिसंबर 2025 को 'नागिन 7' पेश कर रहे हैं। साल का अंत एक धमाकेदार अंदाज में करते हुए, 2025 का यह सबसे बड़ा फैंटेसी ड्रामा स्क्रीन पर दस्तक दे रहा है, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी टेलीविजन पर सबसे प्रतिष्ठित वापसी कर रही हैं। सर्प रानी की पौराणिक विरासत को संभालते हुए, वह सिंहासन पर दावा पेश करेंगी और नागिन-वर्स को इसके अगले ऐतिहासिक अध्याय में ले जाएंगी। प्योर xS39/सर्प-टेनमेंट के साथ भारतीय ग्राहक एंटरटेनमेंट के हिले लेंगे तैयार, यह सीजन नागिन को उसके अब तक के सबसे खतरनाक मुकाबले में झोंक देगा—एक ऐसा युद्ध जो पवित्र महाकथ के तट पर छिड़ेगा। जब एक घातक विषैली आपदा पूरे देश में फैलती है, तब नागिन को उस सच का पता चलता है जो सब कुछ बदल देता है: वह अनंतकुल की चुनी हुई उत्तराधिकारी है, जिसका भारत को पूर्ण विनाश से बचाने के लिए उदय होना है। यह लड़ाई अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है... यह पौराणिक, राष्ट्रीय और अजेय है। प्रियंका चाहर चौधरी मुख्य भूमिका में और नामिक पॉल एक महत्वपूर्ण चरित्र में नजर आएंगे। नागिन 7 का प्रीमियर 27 दिसंबर को होगा और यह हर शनिवार-रविवार रात 8:00 बजे केवल कलर्स और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होगा।

रामा गैलेरिया PEHCHAAN by KADAM के साथ अपनी आर्ट गैलरी का उद्घाटन करने जा रहा है, जो रायपुर में कॉन्टेम्प러리 भारतीय कला की पहचान को नई दिशा देगा

रायपुर। रायपुर स्थित रामा वर्ल्ड के रामा गैलेरिया में PEHCHAAN by KADAM के शुभारंभ के साथ एक प्रीमियम कॉन्टेम्प러리आर्टगैलरी के रूप में औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। यह तीन दिवसीय क्यूरेटेड आर्ट रिजिडेंसी और एक्जीबिशन से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी रामा गैलेरिया की यह पहली सांस्कृतिक पहल है, जिसके जरिए यह स्थान न केवल रायपुर के प्रीमियर लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है, बल्कि मध्य भारत में कॉन्टेम्प러리 कला, क्रिएटिव डायलॉग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के उभरते केंद्र के तौर पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। कदम द्वारा सोच-समझकर क्यूरेट किया गया आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म 'पहचान', जिसकी स्थापना सरिता अग्रवाल ने की है। 'पहचान', इस विश्वास पर आधारित है कि सार्थक कला की शुरुआत समय, धरोसे और सही माहौल से होती है। इस पहल के तहत देशभर से चुने गए दस कलाकारों को एक साथ लाया गया है, जिन्हें अपने कला अभ्यास में गहराई से जुड़ने का दुर्लभ अवसर मिलता है। यह वातावरण एकाग्र और सहयोगी है, जहाँ तुरंत पब्लिक प्रदर्शन का दबाव नहीं होता। क्रिएटिव प्रोसेस की पवित्रता को प्रायोरिटी देते हुए 'पहचान' कलाकारों को यह स्वतंत्रता देता है कि उनके विचार ऑर्गेनिकली विकसित हों, और उसके बाद ही उन्हें वाइड ऑडियंस के साथ बाटा जाए। इस प्रदर्शनी में शामिल कलाकारों में राम डॉंगरे शामिल होंगे, जिन्हें लेयर्ड कैमरायन स्मृति, समय और कल्चरल अवशेषों की पड़ताल होगी। शोख हिफ्जुल कानैरिटेड फेकलोर और जीवन के अनुभवों से प्रेरित हैं। हुकुम लाल वर्मा अपनी इंटरैक्टिव और कलर्स से संचालित एक्सपेरिमेंटल एब्सट्रैक्शन कलाओं के लिए जाने जाते हैं। तुषार वाघेला की कला अभ्यास आस्था सिस्टम और कॉन्टेम्प러리 रियलिटीज पर सवाल उठाती है। सुनील कुमार यादव के मिक्सड-मीडिया कार्य एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के अनकवर, अनदेखे डायमेंशंस को उजागर करते हैं। आशीष कुशवाहा ग्रामीण जीवन और ट्रेडिशनल दृश्य कल्चर से प्रेरणा लेते हैं। चंद्रपाल पांजरे हाथ से मिले वस्त्रों को ग्रामीण मेमरी के ध्यानान्तरक रिफ्लेक्शंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। मुणाल डेएवरीडेके सोशियो- पोलिटिकल जीवन पर टिप्पणी करने वाले सैटिरिकल फ्लोरिड वार्क के लिए पहचाने जाते हैं। निरिश शर्मा की सजीव रचनाएं कॉस्मिक स्पेस और मानव आपसी जुड़ाव की खोज करती हैं। वहीं सुभाषिनल सिंह एक मल्टी डिस्प्लिनरी आर्टिस्ट हैं।

संपादकीय



वंदे मातरम पर बहस

बेहतर होगा कि नेहरू और पूर्व तमाम सरकारों ने जो गलत किया उन पर दो अलग-अलग श्रेत पत्र निकाले जाएं। उससे देश अतीत में उलझी बहसों से बाहर निकल सकेगा। फिर आज की गंभीर समस्याओं पर ध्यान केंद्रित चर्चा हो सकेगी। वंदे मातरम पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने, शायद कटाक्ष में, लेकिन सटीक सुझाव दिया। उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। गांधी ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के नेता लगातार जवाहर लाल नेहरू की गलतियां निकालते हैं। तो क्यों ना इस विषय पर सत्ता पक्ष के मनुमुताबिक समय तय करते हुए संसद में पूरी चर्चा कर ली जाए। बल्कि सुझाव को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा जा सकता है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के पहले की तमाम सरकारों की गलतियों पर खुल कर चर्चा हो। बेहतर तो यह होगा कि नेहरू और पूर्व तमाम सरकारों ने जो गलत किया या जो सही नहीं किया, उन पर दो अलग-अलग श्रेत पत्र निकाले। उन श्रेत पत्रों को राष्ट्रीय अभिलेखागार में रख लिया जाए। लाभ यह होगा कि उसके बाद देश अतीत में उलझी बहसों से बाहर निकल सकेगा। फिर आज की गंभीर समस्याओं पर ध्यान केंद्रित चर्चा हो सकेगी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुछ रोज पहले एक दीक्षांत समारोह में कहा कि इस समय अमेरिका और चीन दोनों अपने मनमाफिक अंतरराष्ट्रीय नियम थोप रहे हैं। इसके बीच भारत मुश्किल में फंसा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है, क्योंकि 'पूर्व सरकारों ने भारत में औद्योगिक ढांचा बनाने पर ध्यान नहीं दिया।' जयशंकर ने कहा कि जिसके पास यह ताकत है, वह दुनिया पर प्रभुत्व जमा रहा है। तो जयशंकर ने आज की विफलताओं को भी पूरी जिम्मेदारी अतीत पर डाल दी। जाहिर है, यह इस पूरी सरकार का नजरिया है। मगर देश के सामने सवाल है कि अतीत में जो हुआ, सो हुआ- अब क्या किया जाए? आखिर अतीत के सत्ताधारियों को जनता ने इसीलिए उनकी आज की हैसियत में पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने देश की अपेक्षाएं पूरी नहीं कीं। इनसे संबंधित सारी बातें सहज स्वीकार की जाएंगी। मगर इन व्यर्थ बहसों से देश को छुटकारा मिलना चाहिए। इसलिए एक बार पूरी बात हो जाए। मगर यह तभी संभव है, अगर वर्तमान सत्ताधारियों की मंशा तुच्छ सियासत से ना प्रेरित हो। ऐसा नहीं है, यह साबित करने का दायित्व उन पर ही है।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करना और साहसिक कदम उठाना

आर. बी. प्रोवर

मानव विकास का संबंध ऊर्जा खपत से है। 1971 में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण शोध पत्र में, अल कुक ने बताया कि आदिम मानव से लेकर आधुनिक तकनीकी मानव तक, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कैसे बढ़ती गई। आदिम मानव को केवल भोजन के लिए ऊर्जा चाहिए होती थी। शिकार के दौर में घर और व्यापार से जुड़ी ऊर्जा जरूरतें भी जुड़ गईं। जब मानव कृषि करने लगा, तो उद्योग, खेती और परिवहन के लिए भी ऊर्जा की मांग पैदा हुई। औद्योगिक और तकनीकी चरणों में भोजन, घर, व्यापार, कृषि और परिवहन के लिए ऊर्जा की जरूरत लगातार बढ़ती गई। वर्तमान समय डिजिटल तकनीकों का युग है, और अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण अतिरिक्त ऊर्जा की मांग करता है। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मानव विकास का सटीक आकलन प्रस्तुत करता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे तीन महत्वपूर्ण संकेतक शामिल हैं। एचडीआई और प्रति व्यक्ति अंतिम ऊर्जा खपत (एफईसी) के बीच संबंध का उपयोग करके यह तय किया जा सकता है कि किसी खास एचडीआई स्तर तक पहुंचने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी। जी20 समूह का सदस्य होने के नाते भारत उन देशों के साथ खड़ा है, जिनका एचडीआई 0.9 से अधिक है। हमारे अनुमानों के अनुसार, ऊर्जा दक्षता और अंतिम उपयोगों के विद्युतीकरण में और सुधार को ध्यान में रखते हुए, 0.9 तक पहुंचने के लिए भारत को प्रति वर्ष लगभग 24,000 टera-वाट-घंटे (टीडब्ल्यूएच) ऊर्जा उत्पन्न करने की आवश्यकता होगी (करंट साइंस, 2022, 122(5), 517-527)। इसमें से लगभग 60 प्रतिशत बिजली के रूप में इस्तेमाल होगी, जबकि शेष भाग का उपयोग इलेक्ट्रोलाइजर में हाइड्रोजन बनाने के लिए किया जाएगा। हाइड्रोजन की जरूरत कठिन, उर्वरक, प्लास्टिक जैसे क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने के लिए होती है। जब हाइड्रोजन उत्पादन की वैकल्पिक तकनीकें बढ़े पैमाने पर विकसित हो जाएंगी, तो बिजली की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। 2023-24 में बिजली उत्पादन लगभग 1950 टera-वाट-घंटे था, और हाल के वर्षों में सीएजीआर लगभग 4.8 प्रतिशत रहा है। इस स्तर पर विकास दर बनाए रखते हुए, चार से पांच दशकों में प्रति वर्ष 24,000 (टीडब्ल्यूएच) बिजली का उत्पादन संभव होगा। हालांकि, इसमें दो जटिलताएँ हैं। सबसे पहले, भारत को अपने ऊर्जा मिश्रण को कार्बन-मुक्त बनाना होगा। इसलिए बिजली उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ अंतिम उपयोगों का विद्युतीकरण और ऊर्जा मिश्रण का पुनर्गठन भी जरूरी है। वर्तमान में अंतिम ऊर्जा खपत (एफईसी) में बिजली की हिस्सेदारी लगभग 22 प्रतिशत है, जिसे काफी बढ़ाना होगा। आज का ऊर्जा मिश्रण मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है, जबकि इन्हें ऐसे ऊर्जा स्रोतों से बदलना होगा जिनसे कार्बन उत्सर्जन न हो। इसका मतलब है कि भारत को जलविद्युत, परमाणु, सौर और पवन ऊर्जा से अधिक बिजली पैदा करनी होगी। भारत में जलविद्युत और पवन ऊर्जा की क्षमता सीमित है। देश की आबादी घनी है, इसलिए सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिए बहुत बड़े भू-भाग को अलग करना आसान नहीं है। हालांकि जल, सौर और पवन ऊर्जा की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन केवल ये स्रोत मिलकर भी 0.9 से अधिक एचडीआई हासिल करने के लिए जरूरी ऊर्जा स्तर उपलब्ध कराने में पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन को तेजी से बढ़ाना होगा। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता, तब तक भारत को कुछ हद तक जीवाश्म ईंधनों का उपयोग जारी रखना पड़ेगा।

विचार-पक्ष

आधुनिक भारत के शिल्पकार श्रद्धेय अटलजी, अंत्योदय के थे साधक

अरुण साव, उपमुख्यमंत्री



भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वह पितातुल्य अभिभावक थे। ज्योतिपुंज अटल जी राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह निरहंकारी एवं ध्येयनिष्ठ व्यक्तित्व से लोगों के हृदय में बसे रहे वह देवदुर्लभ है। सहज-सरल, धोती कुर्ता पहने वह लोगों के बीच इतने सामान्य रूप में उपस्थित होते थे कि उनसे मिलने और अपनी बात रखने में कभी किसी कार्यकर्ता या सामान्य जन को जरा भी संकोच नहीं होता था।

भारत रत्न छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के ऐसे नायक थे, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने कृतित्व से प्रेरित करते रहेंगे। आज सामाजिक, राजनीतिक एवं समाज जीवन के अनेक क्षेत्र में लक्ष्यावधि लोग अटल जी की प्रेरणा से राष्ट्रकार्य में अपनी श्रेष्ठतम भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वह पितातुल्य अभिभावक थे। ज्योतिपुंज अटल जी राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह निरहंकारी एवं ध्येयनिष्ठ व्यक्तित्व से लोगों के हृदय में बसे रहे वह देवदुर्लभ है। सहज-सरल, धोती कुर्ता पहने वह लोगों के बीच इतने सामान्य रूप में उपस्थित होते थे कि उनसे मिलने और अपनी बात रखने में कभी किसी कार्यकर्ता या सामान्य जन को जरा भी संकोच नहीं होता था। अटलजी के व्यक्तित्व में बहुमुखी प्रतिभा थी। कवि हृदय लेखक एवं पत्रकार के रूप में उन्हें मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य एवं स्वदेश जैसे समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को राष्ट्रीयता से ओतप्रोत अपनी पत्रकारिता से सिंचने का जो पुनीत कार्य उन्होंने किया वह आज भी देश और समाज को दिशा दे रहा है। एक कुशल राजनेता के रूप में अंत्योदय के वह अहर्निश पुजारी के रूप में आजीवन राष्ट्रसंधान में जुटे रहे। अटल जी आधुनिक भारत के वह महान शिल्पकार थे जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,



स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान जैसे अंत्योदय के अनुष्ठान से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की अवरिक्त धारा पहुंचाई। सड़कें किसी भी क्षेत्र की प्रगति की सूचक होती हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं ने दूरस्थ और अभावग्रस्त क्षेत्र तक समृद्धि और अक्सर पहुंचाने का काम किया है। सर्वशिक्षा अभियान के जरिए हर बच्चे को स्कूल तक ले जाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ।

अटल जी के जीवन में राष्ट्र निर्माण के अनुपम सूत्र समाए हुए थे। विपक्ष और अन्य प्रतिस्पर्धी दलों के नेता भी उनसे प्रभावित होते थे तथा उनसे आवश्यक सुझाव लिया करते थे। दलगत भवना से ऊपर उठकर वह राष्ट्रहित में सदैव खड़े रहे। विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ जाने के कारण राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार उनके भीतर रहा वह आजीवन उनकी कविताओं तथा उनके कृतित्व में प्रकट हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में कई बार लोग मनभेद कर लेते हैं, लेकिन उनके हृदय में किसी के प्रति कभी मन में विकार नहीं रहा। उनकी सहजता के कारण ही भिन्न विचारधारा के लोगों में भी उनकी स्वीकार्यता थी। हमारे छत्तीसगढ़ की 31 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या

जनजातीय समाज से आती है। देश में कई दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने जनजातीय समाज को हमेशा वोटबैंक की तरह उपयोग किया, लेकिन उनका उत्थान कभी प्राथमिकता में नहीं रहा। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में केंद्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की। आज छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तर पूर्व समेत विभिन्न राज्यों में जनजातीय समाज के उत्थान हेतु अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कथित आर्थिक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। अटलजी का मानना था कि अधोसंरचना विकास किसी भी राष्ट्र की धमनियों की तरह होता है। उन्होंने कई ऐसे क्षेत्र में निजी क्षेत्र की उद्यमिता को बढ़ावा दिया जो लंबे समय तक गैरप्रतिस्पर्धी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही आरक्षित मान लिए गए थे। इससे देश की अर्थव्यवस्था में गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ।

माननीय अटलजी की दूरदृष्टि से छत्तीसगढ़ के निर्माण का वह संकल्प पूर्ण हुआ जिसके लिए हमारे

पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों के लिए यह वर्ष राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। ऐसे में प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने राज्य निर्माता अटलजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। हमारी सरकार के प्रत्येक निर्णय में अटलजी के सुशासन का दर्शन होता है। वह चाहे किसानों की आमदनी दोगुनी करने से जुड़े अनेक निर्णय हों, जिनमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी, श्रीअन्न, दलहल, तिलहन एवं औषधीय खेती को प्रोत्साहन हो या फिर जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन अन्नदाता के प्रति हमारी प्राथमिकता को साबित करता है।

मातृशक्ति के आर्थिक स्वावलंबन के लिए महतारी वंदन योजना एवं महतारी सदन के निर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ में हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता श्रमिकों के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण राशि एवं चरण पादुका जैसे कल्याणकारी निर्णयों के पीछे मोदी जी गारंटी एवं अटलजी के सुशासन का संकल्प ही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सुशासन एवं अधिकरण विभाग का गठन किया है। ई-ऑफिस जैसे नवाचार से शासकीय कामकाज में पारदर्शिता एवं दक्षता आई है। दैनिक जीवन से लेकर उद्यम लगाने से जुड़ी गतिविधियों में सहजता हो इस उद्देश्यों से हमारी डबल इंजन सरकार ने लगभग चार सौ नीतिगत सुधार किए हैं। यह छत्तीसगढ़ को सुशासन के बेहरीन मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करता है। आज देश के प्रधानसेवक एवं विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी एवं छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय विकसित भारत एवं विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में जुटे हैं, संकल्प से सिद्धांती का यात्रा सही मायने में अटलजी की प्रेरणा से ही संभव होगी। यही उन्हें सच्ची अदरार्जलि होगी।

- लेखक : अरुण साव, उपमुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

यह तो आजादी के बाद से चली आ रही परंपरा है

सुनील दास

देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव सबसे ज्यादा अहम होते हैं। यानी लोकतंत्र है तो समय पर चुनाव होने चाहिए। इसलिए देश व राज्यों में हर पांच साल में चुनाव होते हैं। चुनाव राजनीतिक दल लड़ते हैं और कई दलों में जनता किसी एक दल को सत्ता सौंपती है यानी जनहित व राज्य हित व देश हित के काम करने के लिए जनता एक राजनीतिक दल को चुनती है। राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसके अलावा राज्य व देश में राजनीतिक दल को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसके लिए आजादी के बाद से व्यवस्था यही है कि राजनीतिक दलों को दान दिया जाए। दान बढ़े बढ़े औद्योगिक घराने देते हैं। इसके अलावा पार्टी सदस्यता सहित कई तरह से पार्टी का फंड जुटाया जाता

है। सब जानते हैं कि इसके लिए जायज से लेकर नाजायज तरीके काम में लाए जाते हैं। भाजपा ने चंदे की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए इलेक्टोरल बांड की व्यवस्था की थी। पुरानी व्यवस्था से यह व्यवस्था ठीक मानी गई लेकिन इसके लिए बनाई गई योजना को सुप्रिम कोर्ट ने रद्द की तो उसके बाद से पुरानी व्यवस्था से ही राजनीतिक दलों को चंदा मिल रहा है या दान मिल रहा है। राजनीतिक दलों के मिले दान व चंदा के आंकड़े सामने आए तो इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि ट्रस्टों की ओर से राजनीतिक दलों को दान की गई कुल धनराशि का 3112 करोड़ यानी 82 प्रतिशत से अधिक धन भाजपा को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 24-25 में 9 चुनावी ट्रस्टों ने राजनीतिक दलों को 3811 करोड़ रुपए दान किया है। इसका 82 प्रतिशत भाजपा को मिला है, 299 करोड़ रुपए यानी आठ प्रतिशत

कांग्रेस को मिला है और बाकी राजनीतिक दलों को 400 करोड़ यानी 10 प्रतिशत मिला है। राष्ट्रीय दलों में प्रमुख भाजपा व कांग्रेस हैं। जो भी राष्ट्रीय दल होते हैं, उनको क्षेत्रीय दलों की तुलना में औद्योगिक घरानों से ज्यादा दान मिलता है। प्रमुख राष्ट्रीय दलों में जो केंद्र में सत्ता में होता है और राज्यों में सत्ता में होता है, उनको राजनीतिक घरानों से स्वाभाविक रूप से दान ज्यादा मिलता है। यह परंपरा तो कांग्रेस के समय से चली आ रही है। जब कांग्रेस केंद्र व ज्यादातर राज्यों में सत्ता में बढती थी तो उसको सबसे ज्यादा दान औद्योगिक घरानों से मिला करता था। तब भाजपा को कांग्रेस से कम दान मिला करता था क्योंकि वह न केंद्र में न ही राज्य में सत्ता में थी तब भाजपा इस बात को शिकायत नहीं करती थी कि कांग्रेस को ज्यादा चंदा मिलता है, हमको कम मिलता है। ऐसे में तो हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं। भाजपा ने अपने

आपको को कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश किया, मोदी के नेतृत्व में केंद्र व राज्यों में चुनाव जीते उसके बाद औद्योगिक घरानों ने उसे चंदा देना शुरू किया। और आज सबसे ज्यादा दान उसे मिल रहा है तो इसलिए ज्यादा दान मिलता है। प्रमुख राष्ट्रीय दलों में जो केंद्र में सत्ता में होता है और राज्यों में सत्ता में होता है, उनको राजनीतिक घरानों से स्वाभाविक रूप से दान ज्यादा मिलता है। यह परंपरा तो कांग्रेस के समय से चली आ रही है। जब कांग्रेस केंद्र व ज्यादातर राज्यों में सत्ता में बढती थी तो उसको सबसे ज्यादा दान औद्योगिक घरानों से मिला करता था। तब भाजपा को कांग्रेस से कम दान मिला करता था क्योंकि वह न केंद्र में न ही राज्य में सत्ता में थी तब भाजपा इस बात को शिकायत नहीं करती थी कि कांग्रेस को ज्यादा चंदा मिलता है, हमको कम मिलता है। ऐसे में तो हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं। भाजपा ने अपने

सच्चाई है। राजनीतिक दलों के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना चुनाव जीतने के लिए जरूरी होता है, इसलिए हर राजनीतिक चुनाव पांच साल में जरूर जीतना पड़ता है। चुनाव जीतने पर ही राजनीतिक दल आर्थिक रूप से मजबूत होता है। जो दल चुनाव नहीं जीता पाता है, वह हर तरह से कमजोर होता जाता है। चुनाव जिताने की जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व की होती है। यदि वह एक चुनाव नहीं जीता पाता है तो उसके लिए दूसरा चुनाव जीतना बहुत जरूरी होता है क्योंकि चुनावी हार का राजनीतिक दल पर कई तरह से बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि राजनीतिक नेतृत्व दूसरी बार भी चुनाव नहीं जीता पाता है तो नेता पार्टी छोड़कर जाने लगते हैं, दान देने वाले दान देना कम करने लगते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में तो कांग्रेस तीन चुनाव हार गई है और कई राज्यों में चुनाव कांग्रेस हारती जा रही है।

भाजपा नेहरू विवाद को नहीं छोड़ने वाली

अजीत द्विवेदी

यह इतिहास से ज्यादा राजनीति का सवाल है भाजपा की नजर में पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने बड़े नेता थे? भाजपा को उनको इतना बड़ा नेता बताती है जैसे आजादी से पहले और बाद के सारे फैसले उन्होंने अकेले किए तो कभी इतना छोटा नेता बताती है कि वे अपने लिए एक आदमी का समर्थन नहीं जुटा पाए! एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बताती है कि नेहरू इतने बड़े नेता थे कि उन्होंने देश का विभाजन कराया, 'वोट चोरी' करके देश के पहले प्रधानमंत्री बने, संविधान में तमाम किस्म की गड़बड़ियां कराईं, भारत बड़े को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया आदि आदि। लेकिन दूसरी ओर वही भाजपा कहती है कि नेहरू की इतनी हैसियत नहीं थी कि कांग्रेस की कोई प्रांतीय कमेटी अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का प्रस्ताव करे। सवाल है कि जब नेहरू में इतनी भी ताकत नहीं थी कि कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों में से किसी एक कमेटी से अपने नाम की सिफारिश करा सके और सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने शक्तिशाली थे कि 15 में से 12 कमेटियों ने उनके नाम की सिफारिश की तो देश के विभाजन का फैसला नेहरू ने कैसे कराया? अगर सबसे शक्तिशाली महात्मा गांधी और सरदार पटेल थे तो इसका मतलब यह है कि सारे फैसले उन दोनों ने कराए! भाजपा क्यों नहीं कहती है कि देश के विभाजन से लेकर भारत के हिंदू राष्ट्र नहीं बनने तक और संविधान की गड़बड़ियों से लेकर कश्मीर के विवाद तक सबके लिए जिम्मेदार गांधी और पटेल थे, जो कांग्रेस और देश के सबसे बड़े नेता भी थे?

तभी आजादी से ठीक पहले और तुरंत बाद पंडित नेहरू की क्या स्थिति थी इसको समझने के लिए तीन कहानियां सुनने की जरूरत है:

पहली कहानी भाजपा को बहुत पसंद है। संसद में भी वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुनाई थी और कहा था कि 'वोट चोरी' करके नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वह कहानी असल में ऐसी है कि 1940 से लेकर 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष

थे। दूसरे विश्वयुद्ध की वजह से कांग्रेस के अधिवेशन अनियमित हुए और मौलाना आजाद अध्यक्ष बने रहे थे। 1946 में जब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का फैसला हुआ तो उस समय तक तय हो गया था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वह अंतरिम सरकार का प्रमुख होगा। उस समय तीन दावेदार थे सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी और पंडित नेहरू। इनके अलावा मौलाना आजादी भी अध्यक्ष बने रहना चाहते थे। हालांकि उनको चिट्ठी लिख कर महात्मा गांधी ने कह दिया था कि वे उनकी निरंतरता के पक्ष में नहीं हैं। महात्मा गांधी चाहते थे कि नेहरू अध्यक्ष बनें। लेकिन 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम भेजा। संक्षेप में कहानी यह है कि गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए सरदार पटेल और कृपलानी दोनों मैदान से हटे और नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के एक महीने के बाद वायसराय ने उनको अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। जाहिर है नेहरू अपनी ताकत से अध्यक्ष नहीं बने थे और यह भी जाहिर है कि अगर कोई 'वोट चोरी' हुई थी तो वह उन्होंने नहीं की थी। वह तो गांधी थे, जिन्होंने प्रांतीय कमेटियों की सिफारिशों को रद्दी में डाला और नेहरू को अध्यक्ष बनवाया। तभी सवाल है कि प्रधानमंत्री हों या केंद्रीय गृह मंत्री या दूसरे भाजपा नेता वे इस बात को इसी रूप में क्यों नहीं कहते हैं? वे गांधी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते हैं? दूसरी कहानी आजादी के बाद 1950 के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की है। ध्यान रहे अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और चूंकि सरदार पटेल उन प्रथममंत्री बने थे तो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दो साल आचार्य जेबी कृपलानी ने संभाली। उसके बाद दो साल पट्टाभि सीतारामैया कांग्रेस अध्यक्ष रहे। फिर 1950 का चुनाव आया, जो आजादी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का सबसे चर्चित चुनाव रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आचार्य जेबी कृपलानी को अपने उम्मीदवार के तौर पर पेश किया और दूसरी ओर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उम्मीदवार बन गए। उनको सरदार पटेल का समर्थन था। घमासान मुकाबले में राजर्षि टंडन ने आचार्य कृपलानी को हरा

दिया। यानी सरदार पटेल के उम्मीदवार ने पंडित नेहरू के उम्मीदवार को हरा दिया। इसका मतलब है कि चार साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद कांग्रेस में नेहरू की ऐसी हैसियत नहीं बनी थी कि वे सरदार पटेल से जीत सकें। अब सोचें इस चार साल की अवधि के सारे फैसलों के लिए भी अकेले नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि उस अवधि में भी सबसे ताकतवर पटेल थे। उनको देशी रियासतों के विलय का श्रेय दिया जाता है। लेकिन बाकी गड़बड़ियों का ठीकरा नेहरू के सर फोड़ा जाता है! क्या इन चार वर्षों के तमाम फैसलों के लिए सरदार पटेल बराबर के या कुछ ज्यादा के जिम्मेदार नहीं थे?

तीसरी कहानी देश के पहले और दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव की है। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यकारी राष्ट्रपति थे। आजाद भारत में राष्ट्रपति का पहला चुनाव फरवरी 1952 में हुआ। तब तक सरदार पटेल का निधन हो चुका था। प्रधानमंत्री नेहरू को पसंद चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी थे। वे चाहते थे कि दक्षिण भारत से किसी नेता को राष्ट्रपति बनाया जाए। उनको लग रहा था कि दक्षिण भारत के नेताओं का समर्थन राजगोपालाचारी के नाम पर मिलेगा। लेकिन नेहरू उनके लिए समर्थन नहीं जुटा सके और उनकी इच्छा के विरुद्ध राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। दूसरी बार 1957 में भी नेहरू ने उनकी जगह उप राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाना चाहा लेकिन तब भी कामयाब नहीं हुए और राजेंद्र बाबू दूसरी बार राष्ट्रपति बने। सोचें, 1957 में 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी नेहरू इतने ताकतवर नहीं थे कि अपनी पसंद से देश का राष्ट्रपति बनवा सकें! ये तीनों कहानियां सही हैं और भाजपा को बहुत पसंद हैं। भाजपा के नेता अलग अलग कार्यक्रमों में इसमें खूब मिचं मसाला लगा कर सुनाते भी हैं। अब सवाल है कि जब नेहरू में इतनी ताकत नहीं थी कि वे कांग्रेस की 15 कमेटियों में से एक भी समर्थन अपने लिए जुटा सकें तो फिर उन्होंने देश विभाजन का फैसला कैसे करवा दिया? देश विभाजन का फैसला भी तो उन लोगों ने करवाया होगा, जो ताकतवर थे, जिनको 12 कमेटियों का समर्थन मिला था या जिन्होंने 12 कमेटियों के

समर्थन के बावजूद पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया? सबसे ताकतवर तो गांधी और पटेल थे, फिर देश विभाजन का ठीकरा उनके सर क्यों नहीं फूटता है? वहां क्यों था जो पटेल को हरा सकता है या नेहरू का नाम लिया जाता है? सोचें, सरदार पटेल ने चाह दिया तो नेहरू के उम्मीदवार जेबी कृपलानी को अध्यक्ष नहीं बनने दिया। फिर को राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के हाथों हरा दिया। उनको देशी रियासतों के विलय का श्रेय दिया जाता है। लेकिन बाकी गड़बड़ियों का ठीकरा नेहरू के सर फोड़ा जाता है! क्या इन चार वर्षों के तमाम फैसलों के लिए सरदार पटेल बराबर के या कुछ ज्यादा के जिम्मेदार नहीं थे?

जो सबसे ज्यादा ताकतवर कांग्रेस नेता था उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नेहरू अपनी पसंद से राष्ट्रपति नहीं बनवा सकते थे लेकिन भाजपा कहती है कि सारे फैसले वे कर रहे थे। क्या आज यह कल्पना की जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको चाहें उसको हरा कर कोई दूसरा व्यक्ति भाजपा का अध्यक्ष बन जाए या प्रधानमंत्री मोदी जिसको राष्ट्रपति बनाना चाहें उसकी बजाय कोई दूसरा बन जाए? इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन आजादी से तुरंत बाद ऐसा सच में हुआ था कि प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू अपनी पसंद का कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनवा पाए और अपनी पसंद का राष्ट्रपति नहीं बनवा पाए। जाहिर है भाजपा आजादी से ठीक पहले या उसके ठीक बाद जाने अनजाने में हुई तमाम गड़बड़ियों का ठीकरा जान बूझकर, एक राहुल के तहत नेहरू पर फोड़ती है और तमाम अच्छी बातों का श्रेय सरदार पटेल को देती है। असल में इसका तथ्य और तर्क से कोई लेना देना नहीं होता है। वह नेहरू विरोध के सहारे कांग्रेस विरोध को राजनीति करती है। जब तक नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस के शीर्ष पर रहेगा, तब तक यह चलता रहेगा। प्रियंका गांधी वाड़ा ने संसद में कहा कि भाजपा समय तय करके एक बार में नेहरू के बारे में चर्चा कर ले और उसके बाद असली मुद्दों पर चर्चा करे। लेकिन चाहे वे जितना कहें भाजपा इस विवाद को नहीं छोड़ने वाली है। वह किसी भी गड़बड़ी के लिए कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व का नाम नहीं लेगी, गांधी और पटेल का नाम तो कतई नहीं लेगी।



किसानों से धान का एक-एक दाना खरीदने के वादे से सरकार मुकर रही : जितेन्द्र मुदलियार

राजनांदगांव (समय दर्शन)। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार के नेतृत्व में कन्हारपुरी, मोहार, सुरगी और भरंगांव धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। किसानों ने श्री मुदलियार को नापतोल में गड़बड़ी की बात कही। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिनका टोकन जारी हो चुका है, जिन्होंने धान नहीं बेचा है, उन्हें धान बेचने में दिक्कत आ रही है। पूर्व में पटवारियों के द्वारा रकबा समर्पण और अब खरीदी केंद्रों में कट्टा समर्पण के लिए किसानों को कहा जा रहा है, जिस

पर मुदलियार ने प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि किसी प्रकार का समर्पण किसानों से न कराया जाये। प्रबंधकों ने मुदलियार को बताया कि उठाव कम होने के कारण धान खरीदी में दिक्कत आ रहा है, जिस पर तत्काल मुदलियार ने जिला खाद्य अधिकारी से बात कर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चर्चा की। किसानों ने बताया कि पहले 10 एकड़ में 3 टोकन मिलता था, अब 2 ही टोकन मिल रहा है, जिसको लेकर किसानों में संशय की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण कुछ किसान अपना धान नहीं बेच पाये हैं, उन्हें भी फिर से



अवसर मिलना चाहिए। किसानों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं जातिसूचक गाली-गलौज का गंभीर मामला सामने आया है।

भटकना पड़ रहा है। एसडीएम कार्यालय में पहले 15 तारीख तक रकबा संसोधन की व्यवस्था की गयी थी, मगर तिथि समाप्त होने के बाद भी उस तिथि को नहीं बढ़ाया गया है,

इन सब समस्याओं को किसानों ने जितेन्द्र मुदलियार को अवगत कराया। जितेन्द्र मुदलियार ने भाजपा पर आरोप लगाया कि चुनाव के समय भाजपा नेताओं ने किसानों से वायदा किया था कि पंचायतों में केस काउंटर खोलकर 3100 रुपये धान का देंगे, मगर आज तक किसी को भी किसान को धान का 3100 रुपये एकमुश्त पैसा नहीं मिला है। रकबा सुधार में दिक्कत आ रही है, और कई जगह किसानों से कई 40 किलो 900 ग्राम तक धान लिया जा रहा है। शासन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई मापदंड तय नहीं है। हमलों द्वारा 7 रुपये बोरा

शिफ्टिंग का खर्च किसानों से लिया जा रहा है। शासन को हमलों के लिए पर्याप्त हमाली की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसे राज्य शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यह बोझ सीधा किसानों के जेब में पड़ रहा है। मुदलियार ने कहा कि जिस प्रकार अधिकारियों द्वारा किसानों के घर जाकर उनके धान का सत्यापन किया जा रहा है, वह कहीं से उचित नहीं है, उससे किसानों में नाराजगी व्याप्त है। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। किसान की मेहनत को सरकार और उनके अधिकारी संदिग्ध नजरों से देख रहे हैं।

मीडिया के साथियों ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया समाज का संदेश - सनत राठौर



दक्षिणेश्वर काली दरबार जांजीर में आयोजित कार्यक्रम को राठौर क्षत्रिय समाज के निवर्तमान अध्यक्ष ने किया संबोधित

भूमि का आवंटन, पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्व. रामकृष्ण राठौर के नाम पर नामकरण हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ये सभी कार्य समाज के प्रत्येक सदस्य के प्रयास से संभव हो सका है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक में वृहद सम्मेलन संपन्न हुआ, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसी तरह उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में राष्ट्रीय अधिवेशन का सफल क्रियान्वयन हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। राठौर क्षत्रिय समाज को नवगठित कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह 18 जनवरी 2026 को कोरबा में उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न होगा, जिसमें हम सभी की भागीदारी बद्द-चूढ़ कर रहेगी। इससे पूर्व में 4 जनवरी 2026 को ग्राम खोखरा में स्व. चंद्रिका प्रसाद राठौर गुरुजी के सम्मान में महाकाली संगठन की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण एवं विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी की उपस्थिति अपेक्षित है। राठौर समाज के प्रदेश संयोजक केदार पावन धरा जांजीर में संपन्न हुए राठौर क्षत्रिय सभा के प्रांतीय चुनाव अधिवेशन में केंद्रीय नेतृत्व, नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों, प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साहू, क्षेत्रीय विधायक व्यस कश्यप, मीडिया के साथियों सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों के अथक परिश्रम ने हमारी गरिमा पर चार चांद लगाया है।

कलेक्टर ने समय-सीमा बैठक में शासकीय योजनाओं की व्यापक समीक्षा की

धान खरीदी, ई-केवाईसी, प्रशासन गांव की ओर अभियान पर दिए कड़े निर्देश



गरियाबंद (समय दर्शन)। कलेक्टर बीएस उडके ने आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा जिले में संचालित शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्र.शासन गांव की ओर अभियान, मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, धान खरीदी, अवैध परिवहन नियंत्रण, ई-केवाईसी, आवास योजनाएं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने प्रशासन गांव की ओर अभियान की समीक्षा

करते हुए निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधार कार्ड से संबंधित शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इन शिविरों का लाभ ले सकें। उन्होंने शिविरों में प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी स्वीकृत कार्य अनिवार्य रूप से शीघ्र पूर्ण किए जाएं। जनपद सीईओ, आईएस एवं लोक निर्माण विभाग को कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के

निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति के लिए आधार एवं बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य की जाएगी तथा 1 जनवरी से सभी शासकीय पत्रों का आदान-प्रदान ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिला नोडल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह, विशेषकर शनिवार एवं रविवार को भौतिक सत्यापन करें। जिन रड्स मिलों का डीओ कट

चुका है, वहां से धान का उठाव सुनिश्चित किया जाए। षोर्गस उठाव पाए जाने पर संबंधित प्रबंधकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राइस मिलों का पीवी ऐप के चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर निर्देश दिए गए। धान खरीदी में छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने मिलरों एवं परिवहन एजेंसियों के समन्वय से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नियमित एवं सुचारू धान उठाव सुनिश्चित करने तथा लोडिंग प्रक्रिया का शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राजिम महोत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 15 फरवरी तक भव्य रूप में किया जाएगा।

केवीके बेमेतरा में राष्ट्रीय किसान दिवस का भव्य आयोजन, किसानों के योगदान को किया गया नमन

बेमेतरा (समय दर्शन)। कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके), बेमेतरा में देश के पाँचवें प्रधानमंत्री एवं किसान हितैषी नेता स्व. चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर 23 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय किसान दिवस का गरिमामय आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों के योगदान, उनकी मेहनत और देश को खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका को स्मरण करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्री एम.डी. डडसेना, उप संचालक कृषि, बेमेतरा, श्री आकाश शर्मा, सहायक संचालक, क्रेडा, श्री रोशन लाल वर्मा, सहायक संचालक, सी.एस.एस.डी.ए. एवं श्री अभिषेक जायसवाल, सहायक आयुक्त, ट्रायबल विभाग विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत को केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख श्री तोषण कुमार ठाकुर के स्वागत उद्घोषण से हुई।

केवीके प्रमुख श्री ठाकुर ने अपने उद्घोषण में कहा कि राष्ट्रीय किसान दिवस देश के विकास, आत्मनिर्भरता एवं खाद्य सुरक्षा में किसानों के अतुलनीय योगदान को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने कहा कि किसान को अन्नदाता कहा जाता है, इसलिए वर्तमान समय में केवल अधिक उत्पादन ही नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ कृषि उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाया समय की मांग करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन को भी और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इस अवसर पर उप संचालक कृषि श्री एम.डी. डडसेना ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए किसानों को जलवायु सहनशील नवीन किस्मों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए।

किसानों से धान का एक-एक दाना खरीदने के वादे से सरकार मुकर रही : जितेन्द्र मुदलियार

राजनांदगांव (समय दर्शन)। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार के नेतृत्व में कन्हारपुरी, मोहार, सुरगी और भरंगांव धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। किसानों ने श्री मुदलियार को नापतोल में गड़बड़ी की बात कही। उन्होंने बताया कि पूर्व में जिनका टोकन जारी हो चुका है, जिन्होंने धान नहीं बेचा है, उन्हें धान बेचने में दिक्कत आ रही है। पूर्व में पटवारियों के द्वारा रकबा समर्पण और अब खरीदी केंद्रों में कट्टा समर्पण के लिए किसानों को कहा जा रहा है, जिस पर मुदलियार ने प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि किसी प्रकार का समर्पण किसानों से न कराया जाये।



प्रबंधकों ने मुदलियार को बताया कि उठाव कम होने के कारण धान खरीदी में दिक्कत आ रहा है, जिसके कारण धान खरीदी में दिक्कत आ रहा है, जिस पर तत्काल मुदलियार ने जिला खाद्य अधिकारी से बात कर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए चर्चा की। किसानों ने बताया कि पहले 10 एकड़ में 3 टोकन मिलता था, अब 2

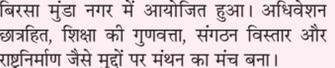
ही टोकन मिल रहा है, जिसको लेकर किसानों में संशय की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण कुछ किसान अपना धान नहीं बेच पाये हैं, उन्हें भी फिर से अवसर मिलना चाहिए। किसानों ने बताया कि जो टोकन है, उसको पुनः जारी करने के लिए भी दिक्कत आ रही है। किसानों को वारिसयान पंजीयन, रकबा संसोधन को लेकर दर-दर

लिया जा रहा है। शासन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई मापदंड तय नहीं है। हमलों द्वारा 7 रुपये बोरा शिफ्टिंग का खर्च किसानों से लिया जा रहा है। शासन को हमलों के लिए पर्याप्त हमाली की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसे राज्य शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यह बोझ सीधा किसानों के जेब में पड़ रहा है। मुदलियार ने कहा कि जिस प्रकार अधिकारियों द्वारा किसानों के घर जाकर उनके धान का सत्यापन किया जा रहा है, वह कहीं से उचित नहीं है, उससे किसानों में नाराजगी व्याप्त है। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। किसान की मेहनत को सरकार और उनके अधिकारी संदिग्ध नजरों से देख रहे हैं। इसका काँग्रेस

पार्टी विरोध करती है। मेहनत और खून-पसीने से धान उगाने वालों किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार कहीं से न्याय संगत नहीं है। इस दौरान मुदलियार ने श्रीमती हेमा देशमुख, नेता प्रतिपक्ष संतोष पिंहे, पूर्व एडम्पेन मन्नाज अग्रवाल, अशोक पंजवानी, उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष आसिफअली, दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यकांत जैन, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष रोहित चंद्राकर, पाषंड मुकेश साहू, पाषंड युवराज भारती, पूर्व पाषंड अवेधस प्रजापति, पूर्व पाषंड महेश साहू, मंडल अध्यक्ष चुन्नाप नियाद, मंडल अध्यक्ष मेघराज चंद्राकर, महामंत्री हेमंत साहू, गुमान हिरम, पूर्व सरपंच दिलीप चंद्राकर, भेषदास साहू, युगल सिन्हा आदि उपस्थित थे।

संक्षिप्त-खबर

अभावपि का 58वां प्रांत अधिवेशन भिलाई में संपन्न, अक्षत श्रीवास्तव बने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य



राजनांदगांव (समय दर्शन)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभावपि) छत्तीसगढ़ का 58वां तीन दिवसीय प्रांत अधिवेशन 19, 20 और 21 दिसंबर को दुर्ग जिले की इस्पात नगरी भिलाई स्थित कला मंदिर, भगवान बिरसा मुंडा नगर में आयोजित हुआ। अधिवेशन छात्रहित, शिक्षा की गुणवत्ता, संगठन विस्तार और राष्ट्रनिर्माण जैसे मुद्दों पर मंचन का मंच बना। अधिवेशन का शुभारंभ ध्वजारोहण व उद्घाटन सत्र से हुआ। इसमें अभावपि के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विकास पांडे और प्रदेश मंत्री अनंत सोनी ने पदभार ग्रहण किया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विशिष्ट अतिथि के रूप में अभावपि के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. आशुतोष मंडावी मौजूद रहे। अधिवेशन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतसु सुखडिया, जनजाति कार्य के अखिल भारतीय प्रमुख निलेश सोलंकी, क्षेत्रीय जनजाति कार्य प्रमुख रामधर और प्रदेश संगठन मंत्री महेश साकेत की विशेष उपस्थिति रही। विभिन्न सत्रों में शिक्षा व्यवस्था, छात्र समस्याओं और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई। अधिवेशन के समापन से पहले संगठनात्मक दायित्वों की घोषणा की गई। इसमें राजनांदगांव के सक्रिय कार्यकर्ता अक्षत श्रीवास्तव को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। संगठन के प्रति उनकी सक्रियता और छात्रहित से जुड़े मुद्दों पर निरंतर कार्य को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके चयन से जिले सहित प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। नवनिर्वाचक प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अक्षत श्रीवास्तव ने कहा कि यह दायित्व उनके लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। वे विद्यार्थियों की समस्याओं, शैक्षणिक सुधार और राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। अधिवेशन का समापन ज्ञान-शील-एकता के उद्घोष के साथ हुआ। इस दौरान छात्रहित और राष्ट्रनिर्माण के लिए निरंतर संघर्ष का संकल्प लिया गया।

एनएमडीसी की किर्न्दुल परियोजना को 'प्लेटिनम अवार्ड' से सम्मानित किया गया



दत्तेवाड़ा किर्न्दुल (समय दर्शन)। एनएमडीसी लिमिटेड के बैलाडिला आयरन और माइन्स, किर्न्दुल कॉम्प्लेक्स को Honour Excellence Awards द्वारा आयोजित भव्य समारोह में Honour Environment & Excellence Award 2025 के तहत मेटल और माइनिंग सेक्टर में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर एक प्रतिष्ठित सम्मेलन भी आयोजित किया गया। यह पुरस्कार किर्न्दुल परियोजना प्रमुख रवीन्द्र नारायण, अधिशासी निदेशक तथा मवनीश शर्मा, उप महाप्रबंधक (पर्यावरण) द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एबी शिवाने, PVSM, AVSM, VSM, पूर्व निदेशक जनरल मैनेकाइन्ड फॉर्सेस और स्ट्राइक कॉर्प्स कमांडर, भारतीय सेना के हाथों प्राप्त किया गया। इस पुरस्कार से एनएमडीसी लिमिटेड की पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार में उच्च दर्शन को मान्यता मिली है, जो विभिन्न परियोजनाओं और पहलों के माध्यम से हासिल किया गया है। यह सम्मान कंपनी की सतत खनन प्रथाओं तथा पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और खनन क्षेत्र में पर्यावरण-अनुकूल संचालन एवं सामाजिक जिम्मेदारी के लिए उसके निरंतर प्रयासों को उजागर करता है। परियोजना प्रमुख ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सभी को बधाई दी।

सुशासन सप्ताह के तहत बेरला में प्रशासन गाँव की ओर अभियान

बेमेतरा (समय दर्शन)। जिले में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्रीमती प्रेमलता पदमकर के मार्गदर्शन में सुशासन सप्ताह का आयोजन निरंतर प्रभावी रूप से किया जा रहा है। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राज.) बेरला सुश्री दीप्ति वर्मा के नेतृत्व में अनुविभाग बेरला अंतर्गत बेरला के गौता मेदान में एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जनसेवा एवं जनसमस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को योजनाओं का लाभ दिलाना तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना रहा। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों की सहभागिता रही, जिन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी समस्याएँ एवं आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर के दौरान राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, खाद्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा पृथक-पृथक स्टॉल लगाए गए। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नागरिकों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा प्राप्त आवेदनों पर मौके पर ही कार्यवाही की गई। कई प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया गया।

खबर-खास

आल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ में युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने धनसाय नायक



बसना(समय दर्शन)। आल इंडिया बंजारा सेवा संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अजय नायक के द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की गई। जिसमें धनसाय नायक को युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद धनसाय नायक ने संगठन को मजबूत कर समाज में राजनीतिक, सामाजिक,सक्रियता से कार्य करने एवं बंजारा समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर कार्य करने की बात कही।

नियुक्ति पश्चात धनसाय नायक ने प्रदेश अध्यक्ष अजय नायक एवं शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट कर धन्यवाद ज्ञापित किया है। युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धनसाय नायक को बनाए जाने पर आल इंडिया बंजारा सेवा संघ के रायपुर संभागीय अध्यक्ष रायमत बंजारा, प्रदेश प्रवक्ता लच्छी राम बंजारा, प्रदेश महासचिव झाडूम परमार, कामेश बंजारा, पंचराम परमार, लखन परमार, दुर्गा नायक एवं सभी सामाजिक बंधुओं ने हर्ष व्यक्त कर बधाई दी है।

पीएमजीएसवाई के तहत 7 नई सड़कों को 13.32 करोड़ की मंजूरी

गरियाबंद (समय दर्शन)। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गरियाबंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को लेकर बड़ी सौभाग्य मिली है। ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के गृह एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने जिले में सात नई सड़कों के निर्माण के लिए 13 करोड़ 32 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

स्वीकृत सभी सड़कें वर्तमान में कच्ची हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। खासकर बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी इन समस्याओं को देखते हुए मंत्री श्री शर्मा ने भाजपा नेताओं एवं ग्रामीणों की मांग को स्वीकार करते हुए यह स्वीकृति दी है। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पक्की सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच भी आसान होगी।

इस विषय में जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने बताया कि बिंदानवाड़ विधानसभा अंतर्गत गरियाबंद जिले के विभिन्न विकासखंडों में सड़क निर्माण कार्यों के लिए कुल 1338.322 करोड़ रुपये की बड़ी स्वीकृति मिली है। इससे क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में आवागमन सुगम होने के साथ विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि देवभोग विकासखंड में सुपेबड़ से परेवापाली तक 1.56 किमी सड़क निर्माण के लिए 1.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं गरियाबंद ब्लॉक में मरदाकला से करीड़गौरी तक 3.30 किमी सड़क के लिए 2.56 करोड़ रुपये तथा रावणडिगी से सेमहरा तक 2.71 किमी सड़क निर्माण हेतु 1.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। मैनपुर विकासखंड में भी कई महत्वपूर्ण सड़कों को स्वीकृति मिली है। इनमें मुड़ोलमाल से स्याहीडोंगरा 3.34 किमी सड़क के लिए 2.84 करोड़ रुपये, अडाड़ी से कोमबुड़ा 3.82 किमी सड़क के लिए 2.51 करोड़ रुपये, कोडोबाट से साल्हेबाट 2.49 किमी सड़क निर्माण हेतु 1.93 करोड़ रुपये तथा भाटीगढ़ से भटावल 0.86 किमी सड़क के लिए 60 लाख रुपये शामिल हैं। जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने ग्रामीणों की ओर से गृह एवं पंचायत मंत्रों विजय शर्मा और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सड़क परियोजनाओं के स्वीकृत होने से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन, व्यापार व शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। आज गरियाबंद में यह कथन साकार होता दिखाई दे रहा है।

कलेक्टर सिंह ने धान उपार्जन केन्द्र मचान्दुर का किया निरीक्षण

दुर्ग (समय दर्शन)। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बुधवार 24 दिसम्बर को धान उपार्जन केन्द्र मचान्दुर का आकरिमिक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पत्र के स्टेज, प्रत्येक स्टेज में बोरो की संख्या, आब तक खरीदे गये धान और उठाव के साथ ही किसानों की टोकन व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने वाहन एन्ट्री पंजी एवं अन्य पंजी संधारण सही नहीं पाये जाने पर समिति प्रबंधक को फरकार लगायी। साथ ही धान पंजीयनों का व्यवस्थित ढंग से संधारण करने के कड़े निर्देश दिये। इस अवसर पर एसडीएम श्री हरवंश सिंह मिरी और तहसीलदार श्रीमती काश्मा यदु भी मौजूद थे। ज्ञात हो कि उपार्जन केन्द्र मचान्दुर में 29139.60 क्विंटल धान की खरीदी हुई। जिसमें मोटा धान की मात्रा 15061.60 क्विंटल, पतला धान की मात्रा 2055.20 क्विंटल एवं सरोना धान की मात्रा 12322.80 क्विंटल शामिल है। खरीदे गये धान की कुल लागत राशि 6 करोड़ 90 लाख 72 हजार 816 रूपए है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

// निविदा निरस्त करने की सूचना //
इस कार्यालय की निविदा सिस्टम क्र. 316/181140 ज्ञाप क्र. 8345/सा./2025 दुर्ग दिनांक 02.12.2025 जिसका जी क्र. 252605344 का अपरिहार्य कारणों से निविदा निरस्त किया जाता है।
अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग दूरभाष - 0788- 2210876
जी-252605634/9

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में किरंदुल के शेख नजमुल को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य की जिम्मेदारी

दत्तेवाड़ा किरंदुल (समय दर्शन)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छत्तीसगढ़ में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के क्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा में नई नियुक्तियों की गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मखमूर इकबाल ने किरंदुल निवासी भाजपा के समर्पित एवं सक्रिय कार्यकर्ता शेख नजमुल को



अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति का सदस्य नियुक्त किया है। शेख नजमुल इससे पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष

के पद पर रहकर सफलतापूर्वक सेवा दे चुके हैं। इस नियुक्ति से क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मंडल अध्यक्ष विजय सोद्वी ने कहा कि शेख नजमुल ने पूर्व में संगठन में विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है और उन्हें यह नई जिम्मेदारी मिलना संगठन के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य की यह जिम्मेदारी

मिलने पर शेख नजमुल ने संगठन एवं शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मखमूर इकबाल, प्रभारी मंत्री केदार करयप, सांसद महेश करयप, विधायक चैतराम अटामी, जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता, मंडल प्रभारी सत्यजीत सिंह चौहान सहित भाजपा के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि इस दायित्व को निष्ठा, समर्पण और अनुशासन के साथ निभाते हुए पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष धर्मपाल मिश्रा, मंडल महामंत्री विक्रम नाहक, मोहित धवन, पूर्व मंडल महामंत्री संजोव दास सहित मंडल के अनेक कार्यकर्ताओं ने शेख नजमुल को बधाई दी और उनके उज्वल भविष्य की कामना की।

दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण



गरियाबंद (समय दर्शन)। जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों के सहयोग एवं सशक्तिकरण की दिशा में लगातार सराहनीय पहल की जा रही है। जिला कार्यालय परिसर में कलेक्टर बी.एस. उड्के ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांग हितग्राहियों को आवश्यक सहायक उपकरण एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उन्हें राहत दिलाई। यह सहयोग न केवल उनके दैनिक जीवन को सुगम बनाने में सहायक होगा, बल्कि उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण को भी नई दिशा की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होगा। कलेक्टर श्री उड्के द्वारा ग्राम कोसमबुड़ा के लिलेश्वर ध्रुव, ग्राम जंजर के लोमश कुमार साहू, ग्राम बेलदुकरी के दुर्गा साहू एवं राजीव कुमार साहू को मोटरसाइकल ट्राईसाइकल वितरित किया गया। इन ट्राईसाइकलों के मिलने से दिव्यांगजन अब पहले की तुलना में अधिक सहजता से आवागमन कर सकेंगे और अपनी आवश्यकताओं को पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कर पाएंगे। उन्हें अब दूसरे पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह ग्राम कोचबाय के पुरन लाल जगत, ग्राम पिपरछेड़ी कला के दयालु राम, गरियाबंद के वार्ड क्रमांक 6 के रामजी यदू तथा ग्राम सड़क परसुली के नर्मदा साहू को श्रवण यंत्र प्रदान किए गए। श्रवण यंत्र मिलने से इन हितग्राहियों के जीवन में संचार, शिक्षा एवं सामाजिक संभागिता के नए अवसर खुलेंगे।

धर्मान्तरण के विरोध में बंद रहा दुर्ग शहर

शहर की सभी बड़ी-छोटी मार्केट रही बंद; चेम्बर, कैट के अलावा सामाजिक व धार्मिक संगठनों के सदस्य रहे सक्रिय



दुर्ग (समय दर्शन)। कांकेर के आमाबेड़ में धर्मान्तरण के बाद सामने आए हिंसक घटना और प्रशासनिक भेदभाव के खिलाफ सर्व समाज द्वारा बुधवार को छत्तीसगढ़ बंद के आन्दोलन का दुर्ग शहर में व्यापक असर रहा। फलस्वरूप दुर्ग में बंद पूर्णतः सफल रहा। बंद से आवश्यक सेवाओं को दुकानों को अलग रखा गया था। जिसके चलते मेडिकल दुकानें, नर्सिंग होम व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शहर की इंदिरा मार्केट समेत सभी बड़ी व छोटी मार्केटों के दुकाने व प्रतिष्ठानें बंद रहे। जिसकी वजह से लोगों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बंद के दौरान दुर्ग शहर में किसी भी क्षेत्र से अप्रिय स्थिति की घटना सामने नहीं आई। जिससे बंद शांतिपूर्ण रहा, वहीं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने पुलिस मोर्चा संभाले रही। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर पुलिस की विशेष तैनाती रही। सर्व समाज द्वारा बंद के आन्दोलन को छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, कैट के अलावा विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया था। जिसकी वजह से दुर्ग जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य बंद के दौरान बाजारों में सक्रिय रहे। चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य दुर्ग जिलाध्यक्ष अनूप गटागत के नेतृत्व में सुबह इंदिरा मार्केट में

एकत्रित हुए और मोटरसाइकल रैली निकालकर बंद की स्थिति का लगातार जायजा लेते रहे। इस दौरान चेम्बर पदाधिकारी इंदिरा मार्केट, सराफ बाजार, हट्टी बाजार, गंजपारा, थोक कपड़ा मार्केट पुलगांव, पटेल चौक, स्टेशन रोड, अप्रसेन चौक, शहीद चौक, सिंधी कॉलोनी, राजेन्द्र पार्क चौक, आदर्शनगर के अलावा शहर के अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में पहुंचे, लेकिन बंद के आन्दोलन के चलते चेम्बर पदाधिकारियों को अधिकांश मार्केटों में स्वतः ही दुकानें बंद मिली। कुछ क्षेत्रों में दुकानें खुली भी मिली, तो चेम्बर पदाधिकारियों द्वारा व्यवसायियों

से धर्मान्तरण के खिलाफ अपनी दुकानें बंद रखने का आग्रह कर दुकानें बंद करवाई गईं। बंद के दौरान मोर्चा संभाले दुर्ग जिला चेम्बर के अध्यक्ष अनूप गटागत ने कहा कि कांकेर के आमाबेड़ा की घटना निंदनीय है। जिसके विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर अपना आक्रोश जताया है। श्री गटागत ने कहा है कि दुर्ग शहर पूर्णतः बंद रहा है। व्यापारियों ने स्वतः ही दुकानें बंद रख यह संदेश दिया है कि इस तरह की घटना के खिलाफ व्यापारी हमेशा चेम्बर के साथ खड़े हुए हैं। बंद के दौरान चेम्बर दुर्ग जिलाध्यक्ष अनूप गटागत, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक राठी, प्रहलाद रंगटा, शिव चंद्राकर, जिला महामंत्री कुलदीप सिंह, चैयमैन किशोर जैन, कोषाध्यक्ष आनंद अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम भंडारी, अरुण दुर्गाडू, आशीष सेक्सरिया, दिनेश मारोटी, दिनेश बादानी, महिला चेम्बर अध्यक्ष डॉ. मानसी गुलाटी, महामंत्री नीतू श्रीवास्तव आदि शामिल थे।

राशन के लिए हितग्राही खाद्य विभाग व राशन दुकानों के चक्कर काटने विवश



ई-केवायसी बनी हितग्राहियों की समस्या, खाद्य विभाग भी समस्या समाधान में असमर्थ। दुर्ग (समय दर्शन)। शासन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत बीपीएल और एपीए राशन कार्ड के कई पात्र हितग्राहियों को पिछले दो-तीन माह से राशन दुकानों से राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से हितग्राही राशन दुकानों व खाद्य विभाग का चक्कर काटने विवश है, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। फलस्वरूप खाद्य विभाग की कार्यशैली के खिलाफ हितग्राहियों का आक्रोश बढ़ने लगा है। यही आक्रोश बुधवार को हितग्राहियों का खाद्य विभाग में देखने में सामने आया, जब राशन नहीं मिलने से नाराज हितग्राही

के एक सदस्य का भी ई-केवायसी नहीं होने की स्थिति पर राशन नहीं मिलेगा। इस पर हितग्राहियों ने सहायक खाद्य अधिकारी से सवाल-जवाब भी किया और हितग्राहियों ने कहा कि अभी 6 महीने पहले ही परिवार के सदस्यों का ई-केवायसी करवाया गया था। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों व बच्चों का तकनीकी खामियों की वजह से ई-केवायसी नहीं हो पाया था। अगर परिवार के एक सदस्य का ई-केवायसी नहीं हुआ है, तो परिवार को राशन देना बंद कर देना गरीब परिवार के साथ अन्याय है। शासन व प्रशासन को इसका विकल्प निकालकर राशन कार्डधारियों को राशन आबंटन कर राहत प्रदान करना चाहिए, ना कि राशन देना बंद कर देना चाहिए। हितग्राहियों के सवाल के जवाब में सहायक खाद्य अधिकारी वसुंधरा गुप्ता का कहना था कि ई-केवायसी के इस समस्या के समाधान के लिए ई-केवायसी से छुटे परिवार के बुजुर्ग सदस्यों व बच्चों का आधार कार्ड व परिवार के राशन की छायाप्रति विभाग द्वारा एकत्रित की जा रही है। केवायसी से छुटे ऐसे सदस्यों का लिस्टिंग कर समस्या समाधान के लिए शासन से मार्गदर्शन मांगा जाएगा ताकि कोई भी पात्र हितग्राही राशन लेने से वंचित ना हो सके।

वीवी-जी राम जी योजना के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष ग्रामसभा का आयोजन

दुर्ग (समय दर्शन)। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नवीन योजना विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) - वीवी-जी राम जी के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता के लिए विशेष ग्रामसभाओं के आयोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में जिला एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों के नामांकन के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों में राष्ट्रीय पेसा दिवस के अवसर पर 24 दिसंबर 2025 को आयोजित विशेष ग्रामसभा में वीवी-जी राम जी योजना को एजेंडा में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र को छोड़कर शेष ग्रामों में 26 दिसंबर 2025 को विशेष ग्रामसभा आयोजित कर योजना के प्रावधानों, रोजगार एवं आजीविका से जुड़े अवसरों तथा 2047 तक विकसित भारत के विजन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। विशेष ग्रामसभा के आयोजन के दौरान गणमान्य व्यक्तियों एवं विशेष आमंत्रित अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा तथा ग्रामसभा की तिथि एवं समय का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

बूढ़ा देव ठाना कांटा पठार स्थापना दिवस को लेकर बैठक सम्पन्न



बसना (समय दर्शन)। नाग शक्ति बूढ़ा देव ठाना कांटा पठार पड़ारपाली (भालुकोना) के स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर गाँडी धर्म संस्कृति एवं छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ के संयुक्त तत्वाधान में पिसदा में एक आवश्यक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक को शुरुआत पंडा पुजारी सुदर्शन सिंह ठाकुर गुरुजी द्वारा नेताम परिवार के निवास में गवरा कलश पूजन एवं स्थापना के साथ की गई। इस दौरान ईश्वर गवरा, बूढ़ा देव तथा माता कली कंकाली की विधिवत महाआरती संपन्न हुई। बैठक में आगामी माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर नाग शक्ति बूढ़ा देव ठाना कांटा पठार में एकदिवसीय त्रिशूल स्थापना दिवस एवं महापूजन कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गोंड समाज के सभी लोगों के सेवा, सहयोग एवं सहभागिता से इस धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाया जाएगा। इस अवसर पर गोकुल पोरखर (सरक्षक, गोंडवाना संघ), दीपक जगत (जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गोंडवाना संघ), देवी सिंह मांडवी (सचिव), भारतिको सिदार (सचिव, गाँडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति), विष्णुनाथ हीरा (जिला उपाध्यक्ष), विजय नेताम (ब्लॉक अध्यक्ष, सरायपाली), बलदेव हीरा (उपाध्यक्ष), निमंकर जगत (ब्लॉक अध्यक्ष), श्रवण पोते (ब्लॉक सचिव), युवा प्रभाग उपाध्यक्ष कमल साय सिदार सहित रिशेश नेताम, शिव अत्रि, बुलामणी सिदार, ननकी पोते एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक का समापन कार्यक्रम को सफल बनाने के संकल्प के साथ हुआ।

सुशासन सप्ताह 2025 के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान बड़ेडामा में संपन्न



बसना (समय दर्शन)। सुशासन सप्ताह 2025 अंतर्गत चौथे सप्ताह का कार्यक्रम दिनांक -24 दिसम्बर को बसना विकास खण्ड के ग्राम बड़ेडामा में सम्पन्न हुआ। जिला पंचायत सभापति मोक्ष प्रधान, एस डीएम हरिशंकर पैकरा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जितेन्द्र त्रिपाठी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि मिलाप निराला, बसना जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीयूष सिंह ठाकुर एवं जनपद सदस्य एवं सरपंचो ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत ग्राम पंचायत बड़े डामा में विकास खण्ड के सभी विभागों के स्टाल लगाए गए थे। बसना जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीयूष सिंह ठाकुर ने बताया कि, इस शिविर में विभिन्न विभागों को कुल

चिखली-खैरागढ़ सड़क निर्माण में नाली नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश, जिलाधीश को सौंपा गया ज्ञापन

राजनांदगांव (समय दर्शन)। चिखली से खैरागढ़ तक हो रहे सड़क निर्माण कार्य में ग्रामों के भीतर नाली निर्माण नहीं किए जाने से क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। जनपद क्षेत्र तिलई, पदुमतरा, खपरी, चवेली एवं बोरी सहित अन्य ग्रामों के जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर समस्या को लेकर जिलाधीश जितेन्द्र यादव को ज्ञापन सौंपते हुए सड़क के साथ नाली निर्माण की स्वीकृति की मांग की है।



ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में जिन गांवों से सड़क गुजर रही है, वहां नाली निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है। इससे भविष्य में बरसात के मौसम में जलभराव, गंदगी और आवागमन में परेशानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। ग्रामीणों का कहना है कि बिना नाली के सड़क निर्माण अधूरा और अव्यवहारिक है। जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि स्थल की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टीमेट (प्राकल्पन) में सुधार कर

नाली निर्माण की स्वीकृति दी जाए तथा नाली निर्माण पूर्ण होने के पश्चात ही सड़क निर्माण कार्य कराया जाए। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। जिलाधीश को सौंपा गया ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में जिन गांवों से सड़क गुजर रही है, वहां नाली निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है। इससे भविष्य में बरसात के मौसम में जलभराव, गंदगी और आवागमन में परेशानी की गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। ग्रामीणों का कहना है कि बिना नाली के सड़क निर्माण अधूरा और अव्यवहारिक है। जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि स्थल की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टीमेट (प्राकल्पन) में सुधार कर

गांजा तस्करी के मामले में सरिया पुलिस ने 01 आरोपी को किया गिरफ्तार

सारंगढ़ बिलाईगढ़ - (समय दर्शन)। कंचनपुर बैरियर में वाहन चेकिंग के दौरान उड़सी तरफसे आते सफेद रंग के आर्टिगा कार क्र सीजी 15 एड्ड 1742 से कुल 83 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ था जिस पर थाना सरिया में अफ क्र 275/25 धारा 20 बी ड्रग्स अधिनियम का अपराध दर्ज कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। घटना बाद से गांजा परिवहन में प्रयुक्त आर्टिगा कार क्र एल 15 एड्ड 1742 का मालिक आरिफहूसैन पिता इकबाल अंसारी उम्र 26 वर्ष सा बरवाही थाना सनावल जिला बलरामपुर (छ ग) पार कर रहा था जिससे आज अम्बिकापुर से लाकर पूछताछ करने पर अपने दोस्त पुननदास के साथ उड़सी से गांजा लाकर बिक्री करना स्वीकार किया तथा गांजा लाने हेतु अपने आर्टिगा कार क्र एल 15 एड्ड 1742 को अपने दोस्त पुननदास को देना बताया। आरोपी आरिफ हूसैन को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

गरियाबंद में पीएमजीएसवाई के तहत 7 नई सड़कों को 13.32 करोड़ की मंजूरी

भाजपा नेताओं व ग्रामीणों ने जताया मंत्री विजय शर्मा का आभार

गरियाबंद (समय दर्शन)। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गरियाबंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण को लेकर बड़ी सीमा तक मिली है। ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के गृह एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने जिले में सात नई सड़कों के निर्माण के लिए 13 करोड़ 32 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत सभी सड़कें वर्तमान में कच्ची हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। खासकर बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। इन समस्याओं को देखते हुए मंत्री श्री शर्मा ने भाजपा नेताओं एवं ग्रामीणों की मांग को स्वीकार करते हुए यह स्वीकृति दी है। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पक्की सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच भी आसान होगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने बताया कि बिंदानवागढ़ विधानसभा अंतर्गत गरियाबंद जिले के विभिन्न विकासखंडों में सड़क निर्माण कार्यों के लिए कुल 1338.322 करोड़ रुपये की बड़ी स्वीकृति मिली है। इससे क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में आवागमन सुगम होने के साथ विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि देवभोग विकासखंड में सुपेबेड़ा से परेवापाली तक 1.56 किमी सड़क निर्माण के लिए 1.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं गरियाबंद ब्लॉक में मरदाकला से करीबगरी तक 3.30 किमी सड़क के लिए 2.56 करोड़ रुपये तथा रावणडिगी से सेमहरा तक 2.71 किमी सड़क निर्माण हेतु 1.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। मैं नपुर विकासखंड में भी कई महत्वपूर्ण सड़कों को स्वीकृति मिली है। इनमें मुड़ोलमाल से स्याहीडोंगरी 3.34 किमी सड़क के लिए 2.84 करोड़ रुपये, अडगड़ी से कोमबुड़ा 3.82 किमी सड़क के लिए 2.51 करोड़ रुपये, कोडोभाट से साल्हेभाट 2.49 किमी सड़क निर्माण हेतु 1.93 करोड़ रुपये तथा भाटीगढ़ से भटगांव 0.86 किमी सड़क के लिए 60 लाख रुपये शामिल हैं। जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने ग्रामीणों की ओर से गृह एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सड़क परियोजनाओं के स्वीकृत होने से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन, व्यापार व शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। आज गरियाबंद में यह कथन साकार होता दिखाई दे रहा है।



भाजपा नेताओं एवं ग्रामीणों की मांग को स्वीकार करते हुए यह स्वीकृति दी है। सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पक्की सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच भी आसान होगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने बताया कि बिंदानवागढ़ विधानसभा अंतर्गत गरियाबंद जिले के विभिन्न विकासखंडों में सड़क निर्माण कार्यों के लिए कुल 1338.322 करोड़ रुपये की बड़ी स्वीकृति मिली है। इससे क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में आवागमन सुगम होने के साथ विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि देवभोग विकासखंड में सुपेबेड़ा से परेवापाली तक 1.56 किमी सड़क निर्माण के लिए 1.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं गरियाबंद ब्लॉक में मरदाकला से करीबगरी तक 3.30 किमी सड़क के लिए 2.56 करोड़ रुपये तथा रावणडिगी से सेमहरा तक 2.71 किमी सड़क निर्माण हेतु 1.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। मैं नपुर विकासखंड में भी कई महत्वपूर्ण सड़कों को स्वीकृति मिली है। इनमें मुड़ोलमाल से स्याहीडोंगरी 3.34 किमी सड़क के लिए 2.84 करोड़ रुपये, अडगड़ी से कोमबुड़ा 3.82 किमी सड़क के लिए 2.51 करोड़ रुपये, कोडोभाट से साल्हेभाट 2.49 किमी सड़क निर्माण हेतु 1.93 करोड़ रुपये तथा भाटीगढ़ से भटगांव 0.86 किमी सड़क के लिए 60 लाख रुपये शामिल हैं। जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने ग्रामीणों की ओर से गृह एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सड़क परियोजनाओं के स्वीकृत होने से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन, व्यापार व शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। आज गरियाबंद में यह कथन साकार होता दिखाई दे रहा है।

वरिष्ठ बीजेपी नेता अक्षय गर्ग के निर्मम हत्या के आरोपी पुलिस के गिरफ्त में, रिमांड पर भेजे गए जेल

राजनीति प्रतिद्वंद्विता और पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी हत्या

कोरबा (समय दर्शन)। थाना कटघोरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता एवं जनपद सदस्य अक्षय गर्ग की नृशंका हत्या के मामले को महज 7 घंटे में सुलझा लिया। केसलपुर और कटोरी नगों के आसपास में हुई इस सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए तीन आरोपियों और एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मृतक अक्षय गर्ग ठेकेदारी का कार्य करता था और 23 दिसंबर 2025 को सुबह लगभग 10 बजे अपने इनोवा वाहन से ग्राम कटोरी नगों कैम्प में कार्यस्थल पर मौजूद था। उसी दौरान कार पहिया वाहन से पहुंचे आरोपियों ने लोहे की धारदार टॉंगिया और चाकू से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। सिर, पेट और हाथ में गंभीर चोट लगने से अक्षय गर्ग की हरिकृष्ण अस्पताल कटघोरा में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त टॉंगिया, चापड़, चार पहिया वाहन, मोबाइल फोन और कपड़े बरामद किए हैं। हत्या के पीछे व्यवसायिक और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता प्रमुख कारण बताए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस त्वरित कार्रवाई से कटघोरा पुलिस की सक्रियता की सराहना की जा रही है। ज्ञात हो कि बीते दिन कोरबा जिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ठेकेदार अक्षय गर्ग को हमलावरों ने चाकू और कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से बुरी तरह से ताबड़तोड़ हमला कर मार डाला। 3 हमलावर कार से आए थे। ताबड़तोड़ चारकर मौके से भाग गए थे। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। बीजेपी नेता अक्षय गर्ग क्लस्टर सड़क निर्माण कार्य के सिलसिले में साइड पर गए थे, तभी एक काले रंग की कार में सवार होकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमले में अक्षय गर्ग के हाथ, सिर, गर्दन, पेट, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे घाव लगे हैं। वारदात के बाद गर्ग को तत्काल कटघोरा के स्थानीय अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। जिसकी डॉक्टरों ने पुष्टि की थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का आंशका जताई जा रही थी जो की सही साबित हुई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में शोक के साथ-साथ आक्रोश और भय का माहौल है।



घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी संजीव शुक्ला एवं एसपी सिद्धार्थ तिवारी स्वयं मौके पर पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितिश ठाकुर के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। गवाहों से पूछताछ, तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मिर्जा मुस्ताक अहमद (27) वर्ष, उसके सहयोगी विश्वजीत ओग्ने (21) वर्ष, गुलशन दास (26) वर्ष और एक विधि से संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया कि मिर्जा मुस्ताक ने हत्या की पूरी योजना बनाई थी। विश्वजीत ने टॉंगिया से सिर पर वार किया, जबकि गुलशन दास मृतक की आवाजाही की सूचना देता था। पुलिस ने आरोपियों की

ग्राम सपलवा के नदिया से भारी मात्रा में अवैध रूप से रेत उत्खनन

कोरबा (समय दर्शन)। ग्राम पंचायत सपलवा और पहाड़ गाँव के मध्य पड़ने वाली नदी से इन दिनों भारी मात्रा में अवैध रेत खनन करते देखा गया। रेत खनन कर कई ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकाल कर खरीदी बिक्री किए जाने संबंधी जानकारी ग्राम सपलवा से प्राप्त हुई जिसके संबंध में प्रेस कर्मियों द्वारा स्थान का कवरेज किया गया तो पाया गया की कई ट्रैक्टरों के ट्राला में रेत भरकर ले जाया जा रहा था। मौके पर समाचार संचालन के दौरान एक ट्रैक्टर चालक द्वारा रेत की ट्राली से खाली किया गया तो एक ने बीडियों बनाते देख ट्रैक्टर लेकर रेतों सहित फरार हो गया। अवैध शब्दों में बात करते हुए धमकी देने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 को कॉल कर बुलाया गया तब कही जा कर विवाद की स्थिति शांत हुई। ज्ञात हो की ग्राम पंचायत सपलवा से रेत खनन करवाने की जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें कई ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत उत्खनन कर बिक्री किए जाने की बात सामने आई है। जिला प्रशासन के अवैध रेत खनन पर जिले भर में सख्त कार्यवाही के बाद भी कुछ जंगली क्षेत्रों के नदियों से भारी मात्रा में रेत निकाला और बेचा जा रहा है। साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों में भी इसी रेत का उपयोग किया जा रहा है। बीहड़ जंगली क्षेत्र में बसे होने के कारण कार्यवाही के आभाव में इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और दिन दहाड़े अवैध रेत खनन का काम भारी मात्रा में इनके द्वारा किया जा रहा है।



रेत उत्खनन कार्य में संलग्न एक व्यक्ति द्वारा प्रेस कर्मियों को बीडियों बनाते देख उस और आक्रामक हो गया एवं पत्रकार के कार्य में हस्तक्षेप करते हुए गांली गलौच करने लगा तथा कुछ लोगों को फेंक कर बुलाने लगा और बहुत ही खरी खोटी शब्दों में बात करते हुए धमकी देने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 को कॉल कर बुलाया गया तब कही जा कर विवाद की स्थिति शांत हुई। ज्ञात हो की ग्राम पंचायत सपलवा से रेत खनन करवाने की

छत्तीसगढ़ में बंद रहा मिला-जुला, ईसाई संगठनों ने अपने पर बढ़ रहे हमलों पर जताई चिंता

बिलासपुर (समय दर्शन)। क्रिसमस के ठीक 1 दिन पहले छत्तीसगढ़ बंद का आवाहन सर्व समाज ने किया। छत्तीसगढ़ के 39 व्यापारिक संगठनों ने इसका समर्थन किया के बावजूद बंद का असर मिला-जुला रहा। दुकानदारों ने इतिहास आधे सत्र उठाकर रखे थे। पर बंद के कारण पुष्पधरा व्यापारी गायब थे। दोपहर 2:00 बजे के बाद अधिकतर दुकानें खुल गईं पर मामला इससे कहीं संवेदनशील है। इसी संगठन द कैथोलिक बिशप ऑफ इंडिया सीबीसीआई ने आगामी क्रिसमस के मध्य नजर विभिन्न रज्यों में ईसाई समुदाय को निशाना बनाने और उन पर कथित हमले में चिंताजनक वृद्धि की निंदा की और कहा कि इससे बंद के संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को नुकसान होता है। बिलासपुर, जबलपुर में



सांताक्लास बने लोगों पर हमले हुए और हिंदू संगठनों ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों से क्रिसमस कार्यक्रम आयोजित न करने कहा। भारत की कुल जनसंख्या के मात्र 2.33 ईसाई हैं। पिछले कई दशकों से भारत की आबादी में इसका हिस्सा लगभग यही है फिर धर्मांतरण से ईसाइयों की जनसंख्या में विस्फोटक बढ़ोतरी का खतरा क्यों सबको वास्तविक जान पड़ता है। ईसाइयों की वृद्धि पर पिछली जगणगी के मुताबिक 22ब से घटकर 15ब रह गई फिर भी ईसाई हिंदुओं के लिए खतरा बन गए हैं। ईसाइयों ने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, कुछ रोगियों का इलाज किया उनके स्कूलों से निकलने वाले लाखों हिंदू बच्चे आज चुप हैं...? क्या ईसाई भारत के लोग नहीं हैं सीबीसीआई ने क्रिसमस पर्व के दौरान ईसाई पर बढ़ रही हमले की घटना पर दुःख व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में किसी भी स्कूल में कोई छात्र सांताक्लास बनकर नहीं आएका क्या ऐसा बयान जारी करने वाले बजरंग दल को यह नहीं पता कि अभी स्कूल में छुट्टी चल रही है स्कूलों में हर त्यौहार मना कर छात्रों

के बीच भारत की मिली जुली संस्कृति का जो संदेश दिया जाता है उसके खत्म करने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने ऐसे स्वयंभू नेता के ऊपर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। सीडीबीई के पदाधिकारी ने कहा है कि क्रिसमस केवल एक धर्म का नहीं बल्कि आपसी सौहार्द और सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक है। मसीही समाज के भीतर तो दिवाली, होली, ईद, गुरु पर्व सब मनाया जाता है। आज बंद के दौरान रैली में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करो के नारे लग रहे थे उससे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार स्वयं विरोधाभास से गिर गई। कांग्रेस शासन के दौरान भाजपा स्वयं धर्मांतरण का आरोप लगाती थी अब भाजपा का शासन है तो विहीप और बजरंग दल धर्मांतरण का आरोप लगा रही है।

वैटरनरी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई मीट में देश-विदेश से जुटे भूतपूर्व छात्र

संस्था और छात्रों को आगे बढ़ाने भूतपूर्व छात्रों ने लिया संकल्प

दुर्ग (समय दर्शन)। दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र-छात्राओं का मिलन समारोह एलुमनाई मीट-2025 एवं स्टूडेंट्स डे प्रोफेशनल्स अलाईन्स अगम एलुमनाई विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार कुलपति डॉ. आरआरबी सिंह के मार्गदर्शन और अधिष्ठाता छत्र कल्याण डॉ. मंजू रंज के दिशा-निर्देश में किया गया। सेमिनार में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड,



गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा छत्तीसगढ़ से कुल 400 भूतपूर्व छात्रों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इसके अलावा कतर, कनाडा व अमेरिका से 05 भूतपूर्व छात्र भी सेमिनार का हिस्सा बने। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सेमिनार अहिवारा विधायक डोमनलाल कोसंबाड़, दुर्ग ग्रामीण

विधायक ललित चंद्राकर, वैशाली नगर विधायक रिंकेश सेन, अधिष्ठाता डॉ. संजय शाक्य, डॉ. मनोज गेंदले, डॉ. सुधीर उपरीत, विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. बीपी राठिया अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशेष अतिथिगणों में मीनल सिंह, श्रीमती पायल अग्रवाल, डॉ. केके ध्रुव, ब्रिगेडियर डॉ. अमित रस्तोगी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किया गया विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

बेमेतरा (समय दर्शन)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के आदेशानुसार एवं अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती सरोज नंद दास के मार्गदर्शन एवं श्रीमती अनिता कोशिया रावटे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के दिशानिर्देश पर आज 24 दिसम्बर 2024 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' पर सेवा सहकारी समिति (धान उपजमण्डी) ग्राम बालसमुंद, ग्राम कुसमी व धान उपजमण्डी कुसमी, शासकीय एक उत्सव है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि पशु चिकित्सक अपना काम बड़ी बखुबी निभा रहे हैं। मूक प्राणी की सेवा करना बड़ा पुण्य का कार्य है।

गया कि हर वर्ष 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित) से नागरिकों को जागरूक करने और अधिक प्रचार-प्रसार कर उपभोक्ताओं के लिए इन अधिकारों के बारे में शिक्षित और अपने दैनिक जीवन में उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए यह बताया गया कि इसके तहत वे उपभोक्ता आते हैं जो सामान एवं वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशॉपिंग, मार्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीदी के जरिये किया जाने वाला सभी तरह का ऑनफ्लाई या ऑनलाइन लेन-देन शामिल है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई (छ.ग.)
 // निविदा सूचना //

क्र./परि.शा./न.नि./2025/3245/359 भिलाई दिनांक 19.12.2025

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से निम्नांकित कार्य हेतु स्थानीय पंजीकृत ठेकेदार से मुहरबंद लिफाफा निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत	निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि	निविदा विभाग में पहुंचने की अंतिम तिथि
1	नेहरू नगर ब्रॉज गुरुद्वारा (वैशाली नगर विधानसभा) तरफ के नामकरण हेतु साइन बोर्ड प्रदाय कार्य	2,79,400.00	09.01.2026	12.01.2026
2	नेहरू नगर ब्रॉज सेक्टर 07 (भिलाई नगर विधानसभा) तरफ के नामकरण हेतु साइन बोर्ड प्रदाय कार्य	2,79,400.00	09.01.2026	12.01.2026

निविदा नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com अथवा www.uad.cg.gov.in संचालनालय की वेबसाइट से भी देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता

मोदी की गारंटी पूरा कराने 29 से 31 दिसंबर तक तृतीय चरण काम बंद-कलम बंद निश्चित कालीन आंदोलन हेतु अनुविभाग पाटन के अधिकारी/कर्मचारी संघ द्वारा सौंपा ज्ञापन

पाटन (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आन्दोलन पर मोदी गारंटी अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से मंहगाई भत्ता, जुलाई-2019 से लॉबित डी0ए0एरियर्स को जी0पी0ए0पी0 में समायोजित करने, विभिन्न संघों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने तथा प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना के आधार पर समस्त सेवालाभ सहित 11 स्त्रीय मांगों को लेकर दिनांक 29,30,31 दिसंबर-2025 को तीन दिवसीय निश्चितकालीन शांतिपूर्ण काम बंद-कलम बंद हड़ताल में अनुविभाग पाटन अंतर्गत कार्यरत सभी विभागों के कर्मचारी-अधिकारी शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला दुर्ग(झाड़ामु देवांगन स्कूल जी0ई0रोड दुर्ग) के सामने हड़ताल पर रहने संबंधी ज्ञापन अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय पाटन को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय प्रवक्ता ललित बिजौरा, संरक्षक टिकेन्द्र वर्मा, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव, ब्लाक संयोजक महेंद्र कुमार साहू, संभागीय महामंत्री चंचल विवेदी, पाटन ब्लाक पेंशनर्स संघ अध्यक्ष हीरारिंह वर्मा, सी0एल0भूआर्य, योगेश महिपाल, सतीश शर्मा, डिलेश शर्मा, सी0एल.निपाद, जितेश कुमार वर्मा, नीलमणी वर्मा, झरना दास, प्रहलाद पांडेय, रानू नागरिया, अनिता धुरंधर, रेशमा यादव, प्रवीण शर्मा, मोतीलाल मार्कण्डेय, ढालसिंग साहू सहित सभी विभागों के कर्मचारी/अधिकारीगण उपस्थित थे।

संक्षिप्त-खबर

कांग्रेस नेता आशीष वर्मा के जन्मदिन पर उज्जवा योजना के हितग्राहियों को मिला नया गैस कनेक्शन, नेता प्रतिपक्ष आभाष दुबे ने किया वितरण

पाटन (समय दर्शन)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ताल्कालिक ओ एस डी और कांग्रेस नेता आशीष वर्मा के जन्म दिन के अवसर पर 24 दिसम्बर को नगर पंचायत पाटन के वार्ड क्रमांक 8 के पार्श्व और नेता प्रतिपक्ष आभाष दुबे ने हितग्राहियों को गैस कनेक्शन का वितरण किया। हितग्राहियों को उज्जवा गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर, चूल्हा सहित पूरा कीट वितरण किया गया।

मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के तहत पाटन नगर में हो रही है विकास कार्य - योगेश निक्की भाले

पाटन (समय दर्शन)। नगर पंचायत पाटन के वार्ड क्रमांक 3 में नाली निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया जो कि 400 मीटर का निर्माण कार्य किया जाएगा जिसका भूमिपूजन अध्यक्ष योगेश निक्की भाले ने किया इस दौरान अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन के तहत पाटन नगर में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने की बात कही भूमिपूजन के अवसर पर उपाध्यक्ष निशा योगेश सोनी, लोक निर्माण प्रभारी व पार्श्व केवल देवांगन, वार्ड 1 पार्श्व चंद्रकाश देवांगन, योगेश सोनी, उप अभियंता अर्जुन निर्मल सहित ठेकेदार व वार्डवर्सी उपस्थित थे।

पाटन ने जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन, जनता से 106 आवेदन मिले

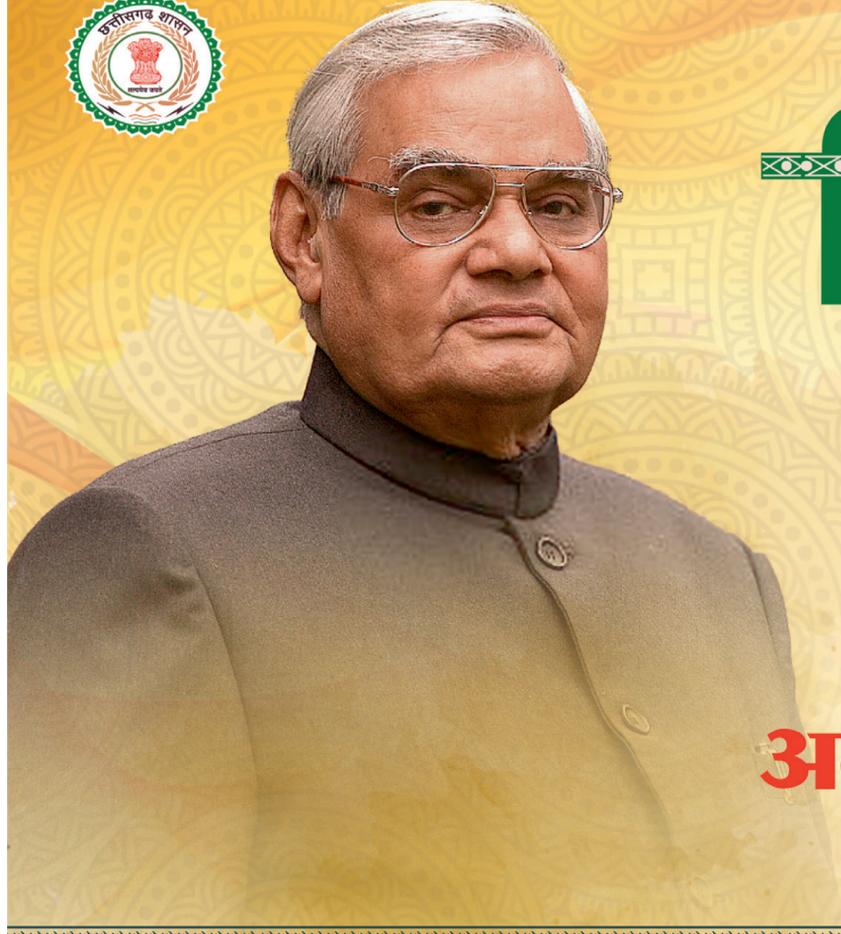
पाटन (समय दर्शन)। नगर पंचायत पाटन द्वारा शासन के आदेशानुसार जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में विकास खण्ड के समस्त विभागों के अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित हुए एवं जनप्रतिनिधि व आम नागरिकों के द्वारा कुल 106 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें से 01 आवेदन का त्वारित निराकरण शिविर में किया गया। उक्त शिविर में नगर पंचायत पाटन के 29 आवेदन एवं अन्य विभाग के 77 आवेदन प्राप्त हुआ, शिविर में नगर पंचायत अध्यक्ष योगेश निक्की भाले, उपाध्यक्ष श्रीमती निशा योगेश सोनी, केवलचंद देवांगन सभापति लोक निर्माण विभाग पाटन, तथा समस्त वार्ड पार्श्व एवं हेमंत कुमार वर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अर्जुन कुमार निर्मल उप अभियंता, संतराम यादव राजस्व उप निरीक्षक, और साथ ही नगर पंचायत कर्मचारी टोकेश्वर डोंगरवार, कैलाश सावर्कर, सोमधाम चन्द्राकर, श्री नेमीचंद देवांगन, गजेन्द्र बया, किशोर वर्मा, गजेन्द्र पटेल, अमीत कुमार व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

राजिम कुंभ (कल्प) मेला 2026 के सफल आयोजन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

गरियाबंद (समय दर्शन)। राजिम कुंभ (कल्प) मेला वर्ष 2026 का आयोजन माघ पूर्णिमा आगामी 1 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 (महाशिवरात्रि) तक आयोजित होना है। कलेक्टर बीएस उडके ने संपूर्ण राजिम कुंभ (कल्प) मेला वर्ष 2026 कार्यक्रम के सुचारू संपादन एवं सर्व विभागों से समन्वय के लिए जिला पंचायत के सीईओ प्रखर चंद्राकर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह अपर कलेक्टर पंकज डाहिरि एवं राजिम के अनुविभागीय अधिकारी विशाल कुमार महाराणा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बालोद जिले में धान की अवैध खरीदी बिक्री की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु किया जा रहा है किसानों के धान का भौतिक सत्यापन

बालोद (समय दर्शन)। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार समर्थन भूलतय पर धान खरीदी को के अंतर्गत धान की अवैध खरीदी-बिक्री पर रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु निगरानी समिति में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा किसानों के घरों में पहुंचकर नियमित रूप से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों द्वारा पहले या दूसरे टोकन में धान के उपरांत पात्रतानुसार शेष रकबे में धान की बिक्री करने हेतु टोकन कटाए जाने पर संबंधित किसानों का भौतिक सत्यापन कर इनके पास धान की उपलब्धता की जांच की जा रही है। जिससे कि कोचियों एवं व्यापारियों के द्वारा किसानों के टोकन से धान की अवैध बिक्री की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।



विश्वासगौरव निर्माण

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता
श्रद्धेय
अटल बिहारी वाजपेयी जी
की जयंती के उपलक्ष्य में
मनाए जाने वाले

सुशासन दिवस की

समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं



सामाजिक-सांस्कृतिक स्थलों के रूप में
115 शहरों में अटल परिसर
का लोकार्पण



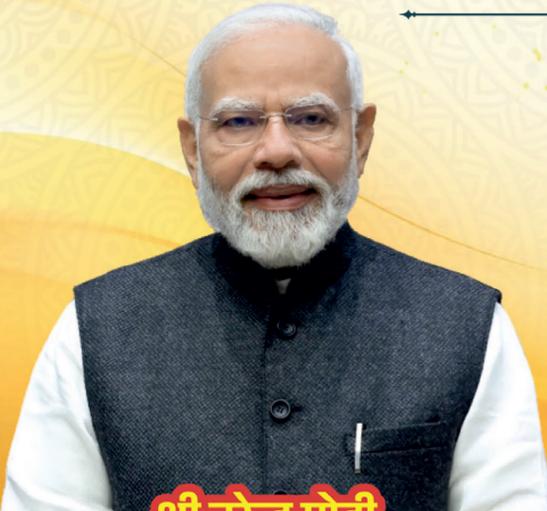
400 से अधिक
प्रशासनिक सुधार से
निवेश की राह आसान



6,090 पंचायतों में
अटल पंचायत
डिजिटल सुविधा केंद्र



पारदर्शिता लाने
सुशासन एवं अभिसरण विभाग
का गठन



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सुशासन के मंत्र से
संवर रहा छत्तीसगढ़



छत्तीसगढ़
जनसंपर्क

Visit us : [f](#) [x](#) [@](#) [/ChhattisgarhCMO](#) [f](#) [x](#) [@](#) [/DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)